● वर्ष-2
● अंक-215
रायपुर, रविवार 30 अप्रैल 2023
● पृष्ठ-6
● मूल्य-3 रु.
samacharpacheesa@gmailÐcom

।। संगच्छध्वम् संवदध्वम् ।।

समाचार पचीसा

राजनीति का जनपक्षकार

अवकाश सूचना

समाचार पचीसा के कार्यालय में 30 अप्रैल रविवार अवकाश रहेगा। समाचार पचीसा का अगला अंक 2 अप्रैल मंगलवार को प्रकाशित होगा।

दुश्मनों को मात देने के लिए तैयार बेटियां

पहली बार भारतीय सेना की तोपखाना रेजिमेंट में हुईं शामिल पांच महिला अधिकारी

भारतीय सेना ने महिला अधिकारियों को आर्टिलरी रेजिमेंट में अनुमति देकर महिलाओं की भूमिका का विस्तार किया है। महिला अधिकारियों के पहले बैच को भारतीय सेना की आर्टिलरी रेजिमेंट में शामिल किया गया। चेन्नई के अधिकारी प्रशिक्षण अकादमी (ह्र्रू) में सफलतापूर्वक प्रशिक्षण पूरा करने के बाद 5 महिला अधिकारी आज आर्टिलरी रेजिमेंट में शामिल हुई हैं। आर्टिलरी की रेजिमेंट में कमीशन की जा रही पांच महिला अधिकारियों (डब्ल्यूओ) को उनके पुरुष समकक्षों (19 पुरुष अधिकारियों को भी आर्टिलरी में कमीशन किया जाता है) के समान अवसर और चुनौतियां प्रदान की जा रही हैं।

इन युवा महिला अधिकारियों को सभी प्रकार की आर्टिलरी इकाइयों में तैनात किया जा रहा है, जहां उन्हें चुनौतीपूर्ण परिस्थितियों में रॉकेट, मीडियम, फील्ड और सर्विलांस एंड टारगेट एक्विजिशन (स्ञ्) और उपकरणों को संभालने के लिए पर्याप्त प्रशिक्षण और एक्सपोजर मिलेगा। छ्व आर्टिलरी आदोष कुमार ने बताया कि रेजीमेंट आर्टिलरी के लिए महिला अधिकारियों का हमारे साथ स्वागत करने का यह एक महत्वपूर्ण अवसर है। हमें उनकी क्षमता पर पूरा भरोसा है और यकीन है कि वे भविष्य में कमांड आर्टिलरी यूनिट सहित अपने संबंधित भविष्य में बहुत अच्छा कार्य करेंगी।

लेफ्टिनेंट रेखा सिंह ने बताया कि मेरे पति के शहीद होने के बाद मैंने आर्मी में शामिल होने का फैसला लिया। आज मेरा प्रशिक्षण पूरा हो गया है और मैं लेफ्टिनेंट बन गई हूं। उन्होंने कहा कि आज मेरे और मेरे परिवार के लिए एक गर्व का क्षण है। मैं अन्य महिला उम्मीदवारों को यही कहना चाहूंगी कि आप स्वयं में विश्वास रखिए और जो करना

चाहती हैं उसके लिए कदम उठाइए। लेफ्टिनेंट महक सैन ने कहा कि यह मेरे लिए बहुत गर्व का क्षण है। मुझे पूरा यकीन है कि हम सभी अपनी भूमिकाओं के साथ न्याय करेंगे और संगठन को अपना सर्वश्रेष्ठ योगदान देंगे।

गलवां हीरो की पत्नी सेना में बनी लेफ्टिनेंट

नई दिल्ली। गलवां में भारतीय और चीनी सैनिकों के बीच साल 2020 में हुई हिंसक झड़प में बिहार रेजीमेंट के नायक दीपक सिंह बलिदान हो गए थे। अब खबर आई है कि नायक दीपक सिंह की पत्नी रेखा सिंह, सेना में शामिल हो गई हैं और वह बतौर लेफ्टिनेंट सेना में कमीशन हुई हैं। खास बात ये है कि रेखा सिंह को पहली तैनाती पूर्वी लद्दाख में एलएसी पर दी गई है। रेखा सिंह ने चेन्नई स्थित ऑफिसर्स ट्रेनिंग एकेडमी से एक साल की ट्रेनिंग पूरी की है, जिसके बाद उन्हें बतौर लेफ्टिनेंट सेना में शामिल किया गया है। बता दें कि लेफ्टिनेंट रेखा सिंह के पति नायक दीपक सिंह बिहार रेजीमेंट की 16वीं बटालियन में तैनात थे और साल 2020 में पूर्वी लद्दाख की गलवां घाटी में चीनी सैनिकों के साथ हुई झड़प में बलिदान हो गए थे। नायक दीपक सिंह को मरणोपरांत 2021 में वीर चक्र से सम्मानित किया गया था।

शादी के बाद शहीद हो गए थे दीपक सिंह

भारतीय सेना ने ट्वीट करके लिखा महिला कैडेट रेखा सिंह, दिवंगत नायक दीपक सिंह की पत्नी, भारतीय सेना में कमीशन हुई हैं। उन्होंने चेन्नई की ऑफिसर्स ट्रेनिंग एकेडमी से अपनी ट्रेनिंग पूरी कर ली है। दीपक सिंह साल 2012 में सेना में शामिल हुए थे और बिहार रेजीमेंट में बतौर नर्सिंग स्टाफ तैनात थे। जनवरी 2020 में उनकी पोस्टिंग लद्दाख में हुई थी लेकिन करीब पांच महीने बाद ही चीनी सैनिकों के साथ मुठभेड़ में नायक दीपक सिंह शहीद हो गए थे। शहीद होने से आठ महीने पहले ही उनकी शादी रेखा सिंह से हुई थी। अब रेखा सिंह ने सेना में शामिल होकर नई मिसाल पेश की है।

चीन-पाकिस्तान का गठजोड़ खतरनाक-नौसेना प्रमुख

नई दिल्ली। भारतीय नौसेना प्रमुख एडमिरल आर हरि कुमार का कहना है कि आत्मनिर्भरता की तरफ से नौसेना तेजी से कदम बढ़ा रही है और 2047 तक भारतीय नौसेना पूरी तरह से आत्मनिर्भर हो जाएगी। चीन और पाकिस्तान की बढ़ती चुनौती पर भी नौसेना प्रमुख ने अपनी बात रखी और कहा कि हिंद महासागर में चुनौतियां लगातार बढ़ रही हैं। नौसेना प्रमुख ने ये भी कहा कि हिंद महासागर में सर्विलांस बढ़ाया गया है। नौसेना प्रमुख ने कहा कि चीन और पाकिस्तान के साझा हित हैं और जिन देशों के साझा हित होते हैं वो आर्थिक और सैन्य तौर पर सहयोग करते हैं। चीन, पाकिस्तान को मिलिट्री हार्डवेयर उपलब्ध करा रहा है और जहां तक हमारी जानकारी है, चीन अगले 10-15 सालों में पाकिस्तान को 50-प्लेटफॉर्म फोर्स बनाने की तैयारी कर रहा है। पाकिस्तानी नौसेना के लिए आठ नई सबमरीन का निर्माण किया जा रहा है, नई ब्रिगेड तैयार की जा रही है और भी कई अन्य तरह के कंस्ट्रक्शन हो रहे हैं। पाकिस्तान तेजी से अपनी नौसेना का आधुनिकीकरण कर रहा है।

वहीं चीन की बात करें तो चीन ने बीते 10 सालों में करीब 148 जहाजों और सबमरीन को अपनी नौसेना में कमीशन किया है। जो कि एक बड़ी संख्या है। इसके अलावा चीन नए युद्धक विमान और जहाजों का भी निर्माण कर रहा है। चीन नया एयरक्राफ्ट कैरियर भी बना रहा है। भारतीय नौसेना की तैयारियों पर एडमिरल हरि कुमार ने कहा कि हम हिंद महासागर में निगरानी बढ़ा रहे हैं, साथ ही रडार सिस्टम को भी मजबूत किया जा रहा है।

नई दिल्ली। कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी पहलवान बजरंग पुनिया, विनेश फोगट, संगीता फोगट और साक्षी मलिक के साथ नई दिल्ली में जंतर मंतर पर अपने विरोध प्रदर्शन के दौरान।

बेंग्लुरू। धारवाड़ में कर्नाटक विधानसभा चुनाव 2023 से पहले एक रोड शो के दौरान केंद्रीय मंत्री प्रह्लाद जोशी के साथ भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा।

सरकार तुष्टिकरण की गिरफ्त में, हिंदुओं का उत्पीड़न हो रहा है

रायपुर। छत्तीसगढ़ प्रदेश भाजपा विधायक दल ने आज बेमेतरा जिले के बिरनपुर पहुंच कर मृतक स्वर्गीय भुनेश्वर साहू के परिजनों से मुलाकात की। बिरनपुर में विधायक दल को मृतक के पिता ने बताया कि धार्मिक हमले में 12-13 युवाओं को भी गंभीर चोट आई है लेकिन पुलिस ने इस मामले में कोई अपराध दर्ज नहीं किया है व लगातार पुलिस कांग्रेस के दबाव में अपराधियों का ही साथ दे रही है। विधायक दल ने वहां के हालात की जानकारी लेने के बाद कहा कि कांग्रेस सरकार बिरनपुर में जिहादी उन्माद की वारदात में भुनेश्वर साहू की नृशंस हत्या के बाद से लगातार तुष्टिकरण की नीति के तहत एक समुदाय के आरोपियों को संरक्षण देने के साथ ही हिंसा के लिए

उकसाने वाले मंत्री समर्थक पर कार्यवाही नहीं कर रही। जबकि हिंदू समाज के बेकसूर युवाओं को संगीन धाराओं के तहत गिरफ्तार कर रही है। उनके परिजनों को मिलने नहीं दिया जा रहा। सरकार आपराधिक मामले में भेदभाव कर रही है। भुनेश्वर की हत्या के सभी आरोपियों को गिरफ्तार नहीं किया गया है। निरपराध हिन्दू युवाओं को गिरफ्तार कर भय का वातावरण बनाया गया है। बेमेतरा में भाजपा विधायक दल से ग्रामीणों ने मुलाकात की। उन्होंने पुलिस पर आरोप लगाया कि डरा धमका कर उनसे जुर्म कबूल कराया जा रहा है। माताओं ने रो रोकर शिकायत की कि उन्हें उनके बच्चो से मिलने नहीं दिया जा रहा है। बिरनपुर में बहुसंख्यक समाज दहशत में है। पुलिस कभी भी किसी भी हिन्दू युवा को पकड़कर उस पर गंभीर अपराध लाद रही है ताकि हिन्दू डरकर बिरनपुर छोड़कर चले जाएं। पूर्व मुख्यमंत्री डॉ. रमन सिंह ने कहा बिरनपुर में हम आकर मृतक के परिजनों से मुलाकात की, वे और गांव का बच्चा-बच्चा इस पूरी घटना में अंजोर यदु नाम के व्यक्ति का उल्लेख कर रहा है जो गांव में खुलेआम घूम रहा है और उसे स्थानीय मंत्री का संरक्षण होने के कारण पुलिस कोई कार्रवाई नहीं कर रही है। उन्होंने कहा बिरनपुर को छावनी बनाकर रखा गया है और गांव वालों को आतंकित किया जा रहा है। मृतक के परिजनों ने लगभग 41 लोगों के नाम पुलिस को दिए हैं लेकिन सिर्फ 11 लोगों पर कार्रवाई हुई बाकी चिन्हित लोगों को छोड़ दिया गया है। इसके बजाय पुलिस दूसरे पक्ष के जो स्वर्गीय भुनेश्वर साहू के साथ के लोग हैं ,उनके परिजन, उनके समाज या गांव के अन्य समाज के लोग हैं उनके खिलाफ 36 से अधिक मामले दर्ज कर चुके हैं ।

प्रमुख समाचार

मोदी सरनेम मामले में अगली सुनवाई दो मई को होगी

अहमदाबाद। सूरत सत्र अदालत के फैसले को चुनौती देने वाली कांग्रेस नेता राहुल गांधी की याचिका पर गुजरात हाईकोर्ट में सुनवाई हुई। इस

दौरान गुजरात उच्च न्यायालय ने राहुल गांधी का प्रतिनिधित्व कर रहे वरिष्ठ वकील अभिषेक मनु सिंघवी से कहा है कि दो मई तक जवाब दाखिल करें। अगली सुनवाई मंगलवार, 2 मई को होगी। इस दिन दोनों पक्ष अपनी अंतिम दलीलें पेश करेंगे। राहुल गांधी के वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने अदालत में अपनी दलील देते हुए कहा, जिस कथित अपराध के लिए कांग्रेस नेता राहुल गांधी को दोषी ठहराया गया है और दो साल की जेल की सजा सुनाई गई है, वह न तो गंभीर है और न ही इसमें नैतिक कदाचार शामिल है। गुजरात उच्च न्यायालय में 2019 के मानहानि मामले में राहुल गांधी की दोषसिद्धि पर रोक लगाने की मांग करते हुए सिंघवी ने ये बातें कहीं।

संजीवनी मामले में आरोपी बने हुए ह गजेन्द्र सिंह शेखावत

जयपुर। राजस्थान उच्च न्यायालय ने केन्द्रीय मंत्री गजेन्द्र सिंह शेखावत को संजीवनी क्रेडिट को-ऑपरेटिव सोसाइटी मामले में आरोपी बताए जाने के संबंध में राज्य सरकार के स्पष्टीकरण को शुक्रवार को रिकार्ड पर लिया। अदालत कथित घोटाले में राजस्थान पुलिस द्वारा दर्ज की गई प्राथमिकी को रद्द करने की शेखावत की याचिका पर सुनवाई कर रही है, जिसमें हजारों निवेशकों को ठगा गया था। तेरह अप्रैल को पिछली सुनवाई में कांग्रेस शासित राज्य के वकील अभिषेक सिंघवी ने शेखावत की याचिका को गलत समझ पर आधारित बताते हुए कहा कि वह इस मामले में राजस्थान विशेष जांच समूह द्वारा दर्ज की गई किसी भी प्राथमिकी में आरोपी नहीं हैं। दो दिन बाद, राज्य सरकार ने एक नयी अर्जी दायर की जिसमें कहा गया है कि सिंघवी की दलील अनजाने में रखी गई क्योंकि वह वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से पेश हुए थे, और उन्हें अदालत में उपस्थित एसओजी के जांच अधिकारी से सहयोग नहीं मिल पाया था।

मोदी केजरीवाल का काम नहीं रोक पाएंगे-सिसोदिया

नई दिल्ली। दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने आबकारी नीति मामले में आप नेता और दिल्ली के पूर्व

उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया की न्यायिक हिरासत 8 मई तक बढ़ा दी है। मनीष सिसोदिया को प्रवर्तन निदेशालय द्वारा जांच किए जा रहे आबकारी मामले में उनकी न्यायिक हिरासत की समाप्ति पर राउज एवेन्यू कोर्ट लाया गया था। न्यायिक हिरासत बढ़ने के बाद सिसोदिया से पत्रकारों ने सवाल भी पूछा। सवालों के जवाब में सिसोदिया ने कहा कि मोदी जी चाहे जितनी कोशिश कर लें, लेकिन दिल्ली में केजरीवाल जी का काम नहीं रोक पाएंगे। ईडी द्वारा जांच की जा रही आबकारी नीति मामले में मनीष सिसोदिया की न्यायिक हिरासत आज 8 मई तक बढ़ा दी गई। इससे पहले दिल्ली की अदालत ने कथित आबकारी नीति घोटाले से संबंधित धनशोधन के एक मामले में आम आदमी पार्टी के नेता मनीष सिसोदिया की जमानत याचिका शुक्रवार को खारिज कर दी।

सुप्रीम कोर्ट पहुंचा आनंद मोहन की रिहाई का मामला

पटना। बिहार के पूर्व सांसद आनंद मोहन की रिहाई का मामला अब सुप्रीम कोर्ट पहुंच चुका है। आनंद को गोपालगंज के तत्कालीन जिलाधिकारी जी. कृष्णैया की हत्या के लिए दोषी ठहराया गया था। कृष्णैयाको 1994 में एक भीड़ ने पीट-पीट कर मार डाला था। अब मारे गए आईएएस अधिकारी जी कृष्णैया की पत्नी ने सुप्रीम

कोर्ट में याचिका दायर कर आनंद मोहन के जेल से रिहाई को चुनौती दी है। बिहार सरकार ने जेल नियमों में संशोधन के बाद गुरुवार सुबह मोहन को सहरसा जेल से रिहा कर दिया। जी. कृष्णैया की पत्नी उमा कृष्णैया ने याचिका में दलील दी है कि गैंगस्टर से नेता बने आनंद मोहन को सुनाई गई उम्रकैद की सजा उनके पूरे जीवनकाल के लिए है और इसकी व्याख्या महज 14 वर्ष की कैद की सजा के रूप में नहीं जा सकती। जी. कृष्णैया ने साफ तौर पर कहा कि जब मृत्यु दंड की जगह उम्रकैद की सजा सुनाई जाती है।

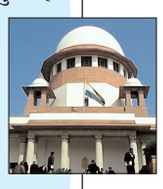

बिना सहमति से शादी तोड़ने का मामला, आज फैसला संभव

नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट पति-पत्नी के बीच आपसी सहमति से विवाह तोड़ने के लिए फैमिली कोर्ट में नहीं जाने की आवश्यकता पर संभवत- एक मई को संविधान के अनुच्छेद 142 के तहत अपनी विशाल शक्तियों का प्रयोग करके व्यापक मापदंडों पर अपना फैसला सुनाएगा। न्यायमूर्ति एसके कौल, न्यायमूर्ति संजीव खन्ना, न्यायमूर्ति एएस ओका, न्यायमूर्ति विक्रम नाथ और न्यायमूर्ति जेके माहेश्वरी की पांच सदस्यीय संविधान पीठ ने 29 सितंबर, 2022 को अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था। अदालत ने अपना आदेश सुरक्षित रखते हुए कहा था कि सामाजिक परिवर्तन में थोड़ा समय लगता है और कभी-कभी कानून लाना आसान होता है लेकिन समाज को इसके साथ बदलने के लिए राजी करना मुश्किल होता है। शीर्ष अदालत ने सुनवाई को दौरान देश में विवाह में एक परिवार की बड़ी भूमिका को स्वीकार किया था।

कर्नाटक चुनाव

पहली बार वोट फ्रॉम होम से लेकर 24 करोड़ की स्याही से वोटिंग

नई दिल्ली। कर्नाटक विधानसभा चुनाव की सरगर्मी बढ़ती जा रही है। सभी पार्टियों के नेता इन अंतिम दिनों में जमकर प्रचार कर रहे हैं। चुनाव आयोग ने भी 10 मई को होने वाले चुनाव की तैयारियां कर ली हैं। इस चुनाव में कई खास चीजें होंगी। जैसे- बुजुर्ग और दिव्यांग मतदाताओं के लिए घर से वोट डालने के लिए एक नई पहल वोट फ्रॉम होम की सुविधा होगी। करीब एक लाख वोटरों ने इस विकल्प का चुनाव किया है।

हर चुनाव में निर्वाचन आयोग कुछ नए प्रयोग करता है और उन्हें लागू भी करता है। ऐसा ही कुछ नया इस बार के कर्नाटक चुनाव में भी देखने को मिलेगा। इस बार बुजुर्ग और दिव्यांग वोटरों के लिए घर से वोट डालने के लिए वोट फ्रॉम होम व्यवस्था शुरू की गई है। यह मतदान पद्धति केवल उन लोगों पर लागू होती है जो या तो अपने घरों तक ही सीमित हैं या उम्र संबंधी बीमारियों से पीड़ित हैं। इस नई मतदान व्यवस्था का राज्य में लगभग 5.71 लाख दिव्यांगों और 80 वर्ष से अधिक आयु के 12,15,763 बुजुर्ग वोटरों को फायदा मिलेगा। कर्नाटक चुनाव आयोग के आयुक्त मनोज कुमार मीणा के मुताबिक, कुल 99,529 लोगों ने वोट फ्रॉम होम विकल्प को चुना है, जिसमें 80 वर्ष से अधिक आयु के 80,250 वरिष्ठ नागरिक और 19,729 दिव्यांग मतदाता शामिल हैं। राज्य के विभिन्न जिलों में बुजुर्ग नागरिकों और दिव्यांग मतदाताओं की संख्या अलग-अलग है। बेंगलुरु के महानगरीय क्षेत्र में कुल 9,152 वरिष्ठ नागरिक और 119 दिव्यांग मतदाता हैं, जबकि कुछ निर्वाचन क्षेत्रों में केवल सात बुजुर्ग नागरिक हैं, जो घर से अपने मत डालेंगे। तमकुरु जिले में सिरा

निर्वाचन क्षेत्र में ऐसे मतदाताओं की संख्या सबसे अधिक है, जिसमें 2,000 से अधिक लोग घर से मतदान करने के पात्र हैं।

वोट फ्रॉम होम व्यवस्था

ऐसे मतदान की प्रक्रिया 29 अप्रैल से शुरू होकर 6 मई तक चलेगी। इस दौरान दो मतदान अधिकारियों, एक पुलिसकर्मी और एक वीडियोग्राफर सहित पांच सदस्यों की एक टीम के साथ प्रत्येक पात्र मतदाता के घर जाएंगे। टीम मतदाता पहचान पत्र की जांच करेगी, एक घोषणापत्र लेगी और उसके बाद एक मतपत्र दिया जाएगा। मतदाता को अपना मत एक गुप्त डिब्बे में डालना होगा और उसे एक लिफाफे में डालना होगा। यदि दौरे के वक्त मतदाता उपलब्ध नहीं होता है, तो टीम दोबारा घर जाएगी। यदि मतदाता दूसरे दौरे के दौरान उपलब्ध नहीं होता है, तो वह मतदान करने का मौका खो देगा।

24 करोड़ रु. की 1,500 लीटर स्याही

इस बीच, चुनाव आयोग ने कर्नाटक विधनसभा चुनाव के लिए 24 करोड़ रुपए में 1,500 लीटर स्याही का ऑर्डर दिया है। यह ऑर्डर मैसूर पेंट्स एंड वार्निश लिमिटेड (एमपीवीएल) को दिया गया है जो स्याही का उत्पादन करने वाली देश की एकलौती कंपनी है। एमपीवीएल हर चुनाव के लिए चुनाव आयोग को इंक की आपूर्ति करती है।

एमपीवीएल के जनरल मैनेजर सी. हर कुमार ने बताया कि उनकी कंपनी ने कर्नाटक विधानसभा चुनाव के लिए 10 एमएल की 150,000 स्याही की बोतलों का ऑर्डर पूरा कर लिया है। इसे चुनाव आयोग को भेज दिया गया है।

कुमार ने कहा कि उन्हें स्याही तैयार करने और भेजने में कम से कम एक महीने का समय लगता है। हमें आमतौर पर चुनाव से दो महीने पहले ऑर्डर मिलते हैं और जरूरत पड़ने पर उसी हिसाब से हम शिफ्ट में काम करते हैं उन्होंने कहा कि आठ घंटे की शिफ्ट में 100 कर्मचारियों के साथ कंपनी 10 मिलीलीटर स्याही की 25,000 बोतलें बनाती है। कंपनी के मुताबिक, 2017 में स्याही की दर 126 रुपये प्रति 10 एमएल बोतल थी 2021 इसमें बदलाव कर 160 रुपये प्रति 10 एमएल बोतल कर दिया गया।

कर्नाटक चुनाव का कार्यक्रम

कर्नाटक में 13 अप्रैल को अधिसूचना जारी होने के साथ ही चुनाव की प्रक्रिया शुरू हो गई थी। प्रत्याशियों ने 20 अप्रैल तक नामांकन दाखिल किया। 21 अप्रैल को नामांकन पत्रों की जांच की गई। वहीं, 24 अप्रैल तक नाम वापस लिए गए। 224 सदस्यीय विधानसभा के लिए राज्य में 10 मई को मतदान होगा। वहीं, 13 मई को राज्य के चुनावी नतीजे आएंगे।

अरनपुर हमले का मास्टरमाइंड नक्सली की फोटो वायरल

आईईडी विस्फोट के बाद जगदीश सहित 12 और नक्सलियों के विरूद्ध अरनपुर में एफआईआर दर्ज

दंतेवाड़ा। जिले के अरनपुर हमले का मास्टरमाइंड नक्सलियों के मिलिट्री दलम का सदस्य पांच लाख का इनामी नक्सली जगदीश जगरगुंडा के ग्राम पूवर्ती निवासी की तस्वीर हथियार एके 47 के साथ वायरल हो रही है। अरनपुर नक्सली वारदात के बाद मिल रही जानकारी के अनुसार अरनपुर आईईडी विस्फोट में जगदीश के द्वारा पूरी वारदात को अंजाम देने के लिए योजना बनाने की बात सामने आ रही है, जिसमें दस जवान और एक ड्राइवर बलिदान हो गए थे।

प्राप्त जानकारी के अनुसार जगदीश पहले सिर्फ कटेकल्याण एरिया कमेटी में सक्रिय था, लेकिन लगातार बड़ी वारदातों को अंजाम देने में सफलता के बाद जगदीश का कैडर बढ़ गया है। जगदीश अब नक्सलियों के मिलिट्री दलम में अहम भूमिका निभा रहा है। अरनपुर हमले की जिम्मेदारी नक्सलियों की दरभा डिवीजनल कमेटी ने ली है। अरनपुर आईईडी विस्फोट के बाद जगदीश सहित 12 और नक्सलियों के विरूद्ध अरनपुर में एफआईआर दर्ज की गई है। पुलिस ने दरभा डिवीजनल कमेटी में सक्रिय नक्सलियों जगदीश, लख्खे, लिंगे, सोमडू, महेश, हिड़मा, उमेश, देवे, नंद कुमार, लखमा, कोसा, मुकेश, चैतू, मंगतू, रनसाय, जयलाल, बामन, सोमे, राकेश, भीमा तथा अन्य के विरूद्ध यूएपीए के तहत एफआइआर दर्ज की है।

किस्टाराम क्षेत्र में सक्रिय 4 नक्सलियों ने किया आत्मसमर्पण

सुकमा। जिले में चलाये जा रहे नक्सल उन्मूलन अभियान के तहत थाना चिंतागुफा के अंदरूनी क्षेत्रों में नवीन सुरक्षा कैम्पों के स्थापित होने से क्षेत्र में हो रहे विकासात्मक कार्यों से प्रभावित होकर प्रतिबंधित नक्सली संगठन में सक्रिय कुल 04 नक्सलियों क्रमश: 01. गड्डोम रमेश (डीएकेएमएस सदस्य), उम्र 25 वर्ष, 02. कुरसम भीमा (मिलिशिया सदस्य) उम्र 25 वर्ष, 03 मड़कम सारा (जनताना सरकार अध्यक्ष साकलेर आरपीसी अन्तर्गत) उम्र 35 वर्ष, 04. माड़वी गंगा (मिलिशिया सदस्य) उम्र 27 वर्ष सभी निवासी थाना किस्टाराम क्षेत्र जिला सुकमा के द्वारा नक्सल ऑपरेशन कार्यालय सुकमा में अति. पुलिस अधीक्षक नक्सल ऑप्स किरण चव्हाण, डिप्टी कमाण्डेन्ट 212 वाहिनी सीआरपीएफ अजय प्रताप सिंह, एवं उप पुलिस अधीक्षक नक्सल ऑप्स कोंटा गिरिजाशंकर साव के समक्ष आत्मसमर्पण कर दिया है। उक्त नक्सलियों को आत्मसमर्पण हेतु प्रोत्साहित कराने में 208 वाहिनी कोबरा आसूचना शाखा, तथा 212 वाहिनी सीआरपीएफ के आसूचना शाखा एवं उप निरीक्षक भावेश शेंडे थाना प्रभारी किस्टाराम का विशेष प्रयास रहा। सभी उक्त आत्मसमर्पित नक्सलियों को राज्य शासन के पुनर्वास नीति के तहत् सहायता राशि व अन्य सुविधायें प्रदाय किया जायेगा।

नक्सलियों के रावघाट एरिया कमेटी ने फेंका पर्चा लगाये आरोप

कांकेर। जिले के अंतागढ़ क्षेत्र के खुड़गांव के पास नक्सलियों के रावघाट एरिया कमेटी के द्वारा पर्चे फेंके गये हैं। पर्चे में पुलिस द्वारा हाल ही में गिरफ्तार किए गए नक्सलियों को ग्रामीण बताते हुए नक्सलियों ने पुलिस पर फर्जी गिरफ्तारी का आरोप लगाया है। पुलिस द्वारा पूर्व में जारी विज्ञप्ति के अनुसार जिन्हें गिरफ्तार किया गया है, उनके विरूद्ध आईईडी विस्फोट से लेकर आगजनी के कई मामले दर्ज हैं। पुलिस पार्टी पर हमला, मोबाइल टावर में आगजनी, वाहनों में आगजनी जैसी वारदातों में गिरफ्तार नक्सली शामिल रहे हैं। क्षेत्र में नया कैंप खुलने से नक्सली बैकफुट पर हैं, इसलिए ऐसे बयान जारी कर दबाव बनाने का प्रयास कर रहे हैं।

गौरतलब है कि महीने की शुरुआत में कांकेर पुलिस ने दो अलग-अलग जगहों से 04 नक्सलियों को गिरफ्तार किया था, जिसमें धुर नक्सल प्रभावित पानी क्षेत्र का नक्सली संगठन के रेंज अध्यक्ष गणेश कड़ियाम भी शामिल था। इसके अलावा 03 अन्य नक्सली भी पुलिस ने गिरफ्तार किए थे। अब नक्सलियों ने लगभग एक माह के बाद इसका खंडन करते हुए पुलिस पर फर्जी गिरफ्तारी के आरोप लगाते हुए आम ग्रामीणों को परेशान करने के आरोप लगाए हैं। नक्सलियों ने पर्चे के माध्यम से अपना बयान जारी करते हुए कहा है कि जिन्हें गिरफ्तार किया गया है, उनका नक्सल संगठन से कोई वास्ता ही नहीं है। नक्सलियों ने पुलिस पर क्षेत्र में कैम्प खोलकर ग्रामीणों को परेशान करने जैसे आरोप लगाए हैं।

भाजपा की बूथ सशक्तिकरण को लेकर बैठक सम्पन्न

भिलाई। भारतीय जनता पार्टी रिसाली मंडल की एक महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई थी। उक्त बैठक में विशेष रूप से रिसाली मंडल के प्रभारी, जिला मंत्री, श्री बृजेन्द्र सिंह जी उपस्थिति थे तथा अध्यक्षता शैलेंद्र शेण्डे शैली मंडल अध्यक्ष जी ने की।

श्री बृजेंद्र सिंह जी द्वारा बैठक में उपस्थित पदाधिकारियों एवं कार्यकर्ताओं के परिचय से अवगत हुए तथा बूथ सशक्तिकरण के अंतर्गत जिन बूथों का बुक(पुस्तिका) अभी तक जमा नहीं हुआ है उसे 2 दिनों के अंदर भिलाई जिला में जमा करने की बात कही तथा 30 अप्रैल, रविवार को देश के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेन्द्र मोदी जी द्वारा मन की बात कार्यक्रम सभी वार्डों में 100 की संख्या में करने की भी बात कही।

इस अवसर रिसाली मंडल में अध्यक्ष शैलेंद्र शेण्डे जी, महामंत्री राजू जंघेल जी, महिला मोर्चा अध्यक्ष श्रीमती रुखमणी साहू जी,पार्षद श्रीमती रमा साहू,श्रीमती सविता धवस जी, वरिष्ठ कार्यकर्ता श्री राकेश शुक्ला जी, अरूण वर्मा जी,भागवत बुंदेला जी, एकनाथ अनुपम जी, अजीत चौधरी जी,विक्की सोनी जी,डामन सार्वा जी, श्रीमती संस्कृति वर्मा जी, उपेंद्र रिगरी जी, बाबूलाल वासनिक जी, अनिल कुमार साहू जी, भूपेंद्र दास जी, श्रीमती ललिता सिंह जी, श्रीमती सुषमा सिंह जी, श्री गोकर्ण मांडले जी, सतीश दुबे जी,शैलेश अवस्थी जी, सचिन गोस्वामी जी, हिमांशु चन्द्राकर आदि उपस्थिति में संपन्न हुआ।

पंचायत सलिहाभांठा में बिजली बंद बूंद-बूंद पानी के लिए ग्रामीण परेशान

■ **जेई बिजली आपूर्ति सुचारू रहने का बोल रहे सफेद झूठ, आक्रोशित उपभोक्ताओं ने कहा कलेक्टर से करेंगे शिकायत**

कोरबा। भीषण गर्मी में बरपाली विद्युत वितरण केंद्र के अंतर्गत आने वाले तुमान फीडर के ग्राम पंचायत सलिहाभांठा वासी एक बार फिर लचर विद्युत व्यवस्था से हलाकान हैं। रात डेढ़ बजे से गुल हुई बिजली दोपहर 12 बजे तक नहीं आई। जहां लोग भीषण गर्मी में बूंद-बूंद पानी के लिए विद्युत आपूर्ति बहाल होने का इंतजार हलाकान हो रहे वहीं जेई विद्युत आपूर्ति बंद नहीं होने का सफेद झूठ बोल बोल रहे। अधिकारियों की निष्क्रियता से आक्रोशित ग्रामीण उपभोक्ताओं ने कलेक्टर से सम्बंधित अधिकारियों के विरुद्ध उचित कार्रवाई की गुहार लगाई है।

देश की ऊर्जा जरूरतों को पूरा करने में महती योगदान देने वाला उर्जानगरी कोरबा की जनता को हर साल लचर विद्युत वितरण व्यवस्था का खामियाजा भुगतना पड़ता है । भीषण गर्मी में ग्रामीण अंचल में लोगों की तकलीफें बढ़ गई है। बरपाली विद्युत वितरण केंद्र के अंतर्गत आने वाले तुमान सब स्टेशन के ग्राम पंचायत सलिहाभांठा जो कि रामपुर विधायक ननकीराम कंवर का गृह ग्राम पंचायत है। बीती रात डेढ़ बजे से बिजली गुल है। रातभर लोग परेशान रहे। विद्युत आपूर्ति बहाल नहीं होने की वजह से फोन डिस्चार्ज हो गया है वहीं बोरवेल से पानी लेने लोग बिजली आने की राह तक रहे। हैरान करने वाली बात तो यह है कि जेई

विद्युत आपूर्ति सुचारू होने की बात कह रहे। उन्होंने एई को भी बिजली बंद होने की सूचना नहीं दी। अधिकारियों के सफेद झूठ से ग्रामीण बेहद आक्रोशित हैं। वे कलेक्टर से सम्बन्धितों के विरुद्ध उचित कार्रवाई करने शिकायत करने की बात कह रहे। ग्रामीणों की मानें आए दिन आधी रात बिजली बंद कर दी जाती है। लोग रतजगा करते हैं।

मोबाईल डिस्चार्ज, नहीं मिल रहा पानी, ग्रामीण परेशान:- खबर लिखे जाने तक तुमान फीडर के पूर्व सांसद स्व.डॉ बंशीलाल महतो के गृह ग्राम एवं रामपुर विधायक ननकीराम कंवर का गृह ग्राम पंचायत में विद्युत आपूर्ति बंद थी। बोरवेल, कूलर, पंखे से लेकर तमाम इलेक्ट्रॉनिक्स उपकरण बिजली पर निर्भर है। जिसकी वजह से लोगों को सुबह से पानी तक नसीब नहीं हुआ है। जल जीवन मिशन का काम ठेकेदार की मौत के बाद वैसे ही अधूरी पड़ी है। मोबाईल चार्ज करने लोगों को बरपाली जाना पड़ रहा।

चित्रा सिनेमा के बड़े पर्दे पर होगी पीएम मोदी की मन की बात

कोरबा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के रेडियो कार्यक्रम मन की बात का 100 वां एपिसोड का प्रदर्शन रविवार 30 अप्रेल 2023 की सुबह 11 बजे शहर में चित्रा सिनेमा के बड़े पर्दे पर किया जाएगा।

प्रधानमंत्री के मन की बात कार्यक्रम के कोरबा जिला संयोजक और भारतीय जनता पार्टी के जिला कोषाध्यक्ष गोपाल मोदी ने यह जानकारी दी है। उन्होंने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लोकप्रिय रेडियो कार्यक्रम ष्मन की बात का प्रसारण प्रतिमाह अंतिम रविवार को विभिन्न संचार माध्यमों से किया जाता है। इस माह मन की बात का 100 वां एपिसोड प्रसारित हो रहा है। यह एपिसोड खास होगा। भाजपा ने पूरे देश में इसके व्यापक स्तर पर प्रसारण-प्रदर्शन की व्यवस्था की है। देश के अलावे पूरी दुनिया में इसे देखा-सुना जाएगा। उन्होंने बताया कि इस विशेष एपिसोड को लेकर देश-विदेश के नागरिकों में भारी उत्सुकता है

भाजपा नेता गोपाल मोदी ने बताया कि जिले में भाजपा के सभी 19 मण्डलों में कार्यक्रम प्रसारण की तैयारी की गई है। पार्टी कार्यकर्ता और नागरिकगण मन की बात कार्यक्रम सुनने के बाद प्रधानमंत्री के वक्तव्य पर आपस में चर्चा भी करेंगे। उन्होंने जिले के सभी नागरिक बन्धुओं से प्रधानमंत्री के मन की बात सुनने के लिए आयोजित किये जा रहे कार्यक्रमों में अधिक से अधिक संख्या में सहभागी बनने की अपील की है।

लंबित मजदूरी भुगतान को लेकर कटघोरा डिवीजन कार्यालय के सामने मजदूरों ने किया धरना प्रदर्शन

1 मई मजदूर दिवस से अनिश्चितकालीन धरना की दी चेतावनी

कोरबा। कोरबा जिले के कटघोरा वन मण्डल में पिछले 3 सालों से लंबित मजदूरी भुगतान को लेकर बड़ी संख्या में जड़गा, एतमा नगर व केंदई रेंज के मजदूरों ने कटघोरा डिवीजन कार्यालय के सामने धरना प्रदर्शन पर बैठे तथा उनके समर्थन देते हुए पाली तानाखार विधानसभा के भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारी भी उनके साथ धरना प्रदर्शन में बैठेए वन विभाग द्वारा संतोषप्रद जवाब न मिलने पर 1 मई मजदूर दिवस से अनिश्चितकालीन धरना की दी चेतावनी।

बतादें कि कटघोरा वनमण्डल अन्तर्गत विभिन्न वन परिक्षेत्रों में तीन वर्षों में कई करोड़ रुपए के निर्माण कार्य विभिन्न योजनाओं से हुए हैं। लेकिन सप्लायर और ठेकेदारों का तो भुगतान रोज हो रहा है लेकिन दो ढाई सौ मजदूरों को छह माहए चार माह काम कराकर भुगतान करना भूल गए । पीड़ित मजदूर कई बार वनमण्डल के चौखट तक अपनी फरियाद लगा चुके हैं वन विभाग के कर्मचारियों के काम कराने के पश्चात इस तरह की गैर जिम्मेदाराना जवाब और डीएफओ की असंवेदन शीलता से त्रस्त होकर मजदूर अपनी खून पसीने की गाढ़ी

कमाई पाने सड़क पर उतरने को आमादा हो गए हैं और आज कार्यालय के सामने धरने पर बैठ गए। उनके साथ भारतीय जनता पार्टी के जिला उपाध्यक्ष संजय भावनानीए कोरबा के पूर्व महापौर जोगेश लाम्बा के साथ बड़ी संख्या में बीजेपी कार्यकर्ता धरना स्थल पर मौजूद रहे। कटघोरा वन मण्डल के एसडीओ संजय त्रिपाठी मौके पर पहुंचे व सभी से बात की लेकिन मजदूर अपनी मांगों को लेकर अड़े रहे। और कार्यालय के पास ही दोपहर का खाना भी बनाया। शाम होते तक वन विभाग द्वारा किसी प्रकार का कोई संतोषजनक जवाब न मिलने पर बीजेपी पदाधिकारियों ने वन मण्डल के संबंधित अधिकारीयो व कर्मचारियों के खिलाफ कटघोरा थाना में शिकायत दर्ज कराई और सोमवार 1 मई मजदूर दिवस को अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन करने व संबंधित वन विभाग के अधिकारियों की गिरफ्तारी की मांग किये जाने का निर्णय लिया।

गौरतलब हो कि 11 अप्रैल को सैकड़ों मजदूरों ने शपथ पत्र बनवाकर लीलार गोस्वामी पूर्व उपाध्यक्ष लघु वनोपज संघ जिला यूनियन कटघोरा की मदद से कुल 11 बिंदुओं के निराकरण की मांग को लेकर वनमण्डल कार्यालय घेराव का ज्ञापन सौपे था। धरना प्रदर्शन में भारतीय जनता पार्टी के कोरबा के पूर्व महापौर व भाजपा के प्रदेश कार्यकारिणी के सदस्य जोगेश लाम्बा, भाजपा प्रदेश उपाध्यक्ष संजय भावनानी, वन लघु वनोंपज संघ के पूर्व उपाध्यक्ष लिलार पूरी गोस्वामी, मनोज जायसवाल, सुनील खांडे, समजीत सिंह, अनुराग दुहलानी व बड़ी संख्या में पुलिस व महिला मजदुर उपस्थित रहे।

छत्तीसगढ़ प्रमुख समाचार

दंतैल हाथियों ने जलके में तोड़े फेंसिंग तार व खंभे

कोरबा। जिले के पसान रेंज के जलके सर्किल में अचानक पहुंचे दंतैल हाथियों ने बीती रात उत्पात मचाते हुए वन विभाग द्वारा जंगल में लगाए गए फेंसिंग तार व खंभे को तोड़ दिया। जानकारी मिलने पर वन विभाग के अधिकारी व कर्मचारी आज सुबह मौके पर पहुंचे और हाथियों द्वारा किये गए नुकसानी की जानकारी। हाथियों के इस उत्पात से वन विभाग को हजारों रूपए का नुकसान उठाना पड़ा है। इससे पहले दंतैल हाथियों ने पसान सर्किल के गांवों में पहुंचकर उत्पात मचाया और ग्रामीणों के घर को तोडने के साथ ही फसल को भी नुकसान पहुंचाया था। दंतैल हाथी कल स्कूल में पहुंचकर भी उत्पात मचाया था। दंतैल हाथियों के लगातार उत्पात से क्षेत्रवासी दहशत में है। वन विभाग द्वारा आसपास के गांव में मुनादी कराकर ग्रामीणों को सतर्क कर दिया गया है। उधर केंदई रेंज के लालपुर में 21 तथा कापानवापारा में 13 हाथी अभी भी विचरण कर रहे है।

आईआर वार्ता में माइनिंग सरदार व ओवरमेन की कमी का मुद्दा उठा

कोरबा। एसईसीएल गेवरा परियोजना में कोयला उत्पादन के लिए कोयला कामगारों पर भारी दबाव बना रहता है। लेकिन यहां माइनिंग सरदार व ओवरमेन सहित कामगारों की कमी है। कामगारों की संख्या बढ़ाने के लिए लगातार मांग की जाती रही है। कल एसईसीएल मुख्यालय में एसईकेएमसी की आईआर वार्ता आयोजित की गई। जिसमें इस मुद्दे को जोर.शोर से उठाया गया और गेवरा परियोजना में नए कामगारों की नियुक्ति करने की मांग की गई। अन्य एरिया से आए कामगारों ने भी अपने.अपने क्षेत्र के समस्याओं को उठाया। केंद्रीय कर्मशाला के दिलीप सिंह व बीण्आरण्सुमन ने एक कामगार की जन्मतिथि गलत होने के मुद्दे को उठाया। केंद्रीय कर्मशाला गेवरा के विकास शुक्ला व एलीन एक्का ने भी बैठक में शामिल होकर कई मुद्दों को रखा। बैठक में केंद्रीय अध्यक्ष गोपाल नारायण सिंह, संदीप चौधरी, संदीप राय, गोपाल यादव, देवंश मिश्रा, ए के अंसारी, रमेश मिश्रा, मनोज ठाकुर सहित कई पदाधिकारी मौजूद थे।

स्वास्थ्य कर्मचारियों की हड़ताल से सेवाएं हुई बाधित

दंतेवाड़ा। जिले के स्वास्थ्य कर्मचारी कोरोना भत्ता व अन्य 19 मांगों को लेकर सयुंक्त संगठन के बैनर तले डाक्टर, पैरामेडिकल स्टाफ, एनएचएम एवं अन्य समस्त 01 हजार 83 स्वास्थ्य कर्मचारी बीते तीन दिनों से हड़ताल पर चले गए हैं, जिसकी वजह से जिले के सभी अस्पतालों में ओपीडी सेवा बंद हो गई है। जिले में जिला अस्पताल के साथ-साथ पांच सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र, 13 प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, 76 उप स्वास्थ्य केंद्रों में स्वास्थ्य सेवा का इस हड़ताल का सीधा असर पड़ रहा है। अति आवश्यक सेवाओं के बाधित होने के बावजूद अभी तक हड़ताल को खत्म करवाने की कोई ठोस पहल नहीं की जा रही है। स्वास्थ्य अधिकारी बीआर पुजारी का कहना है कि कोरोना काल में 70-80 कर्मचारियों को ही भत्ते का भुगतान हुआ है, हड़ताली कर्मचारी इसी भत्ते की मांग को लेकर अड़े हुए हैं।

पीआरसीआई पुरस्कार में बस्तर को प्रथम स्थान मिला

जगदलपुर। बस्तर छत्तीसगढ़ को प्लास्टिक रीसाइक्लिंग कॉन्फ्रेंस एशिया द्वारा पहला स्थान हासिल किया। यह पुरस्कार जिले के स्वच्छता एवं शहर में कचरे के प्रबंधन के क्षेत्र में बस्तर के योगदान को सम्मानित करता है। 28 अप्रैल, 2023 को मुंबई में आयोजित एक कार्यक्रम के दौरान प्लास्टिक पुनर्चक्रण सम्मेलन एशिया (पीआरसीआई) द्वारा पुरस्कार प्रदान किया गया। जिला पंचायत बस्तर ने एचडीएफसी बैंक और सीईई के साथ साझेदारी से संचालित परियोजना के तहत प्लास्टिक कचरे को कम करने, पुनर्चक्रण करने एवं फिर से उपयोग करने के लिए उचित उपाय अपनाए एवं जिले में घर-घर जाकर कचरा इकट्ठा करने, मूल्य स्रोत पर छंटाई करने और कचरे के प्रबंधन के लिए मटेरियल रिकवरी फैसिलिटी की स्थापना जैसी अनेक नवाचारी पहल की है। बस्तर के प्रयासों के फलस्वरूप लोगो के सार्वजनिक व्यवहार में बदलाव आया है, जहां समुदाय सक्रिय रूप से कचरे के प्रबंधन में भागीदार बन रहे हैं।

पढाई के प्रति समर्पित शिक्षकों का गजब का जज्बा

पाटन। इस प्रशिक्षण व टेस्ट परीक्षा को सफल बनाने व बच्चों को कुशल तरीके से सिखाने हेतु पढाई के प्रति समर्पित शिक्षक को जन्मभूमि कर्मचारी सेवा समिति के द्वारा सम्मान किया गया । अपने कर्तव्य स्थल पर भी पुरा काम करने बाद भी निस्वार्थ भाव से बच्चों को नवोदय परीक्षा के लिए अपने द्वारा तैयार किये गये पेपर कटिग टार दर्पण आदि पाठय समाग्री को लेकर समिति के सदस्यों के एक सुचना पर उपस्थित होकर बच्चों को बच्चे की तरह ही बनकर अपना शत प्रतिशत ज्ञान देने का भरसक प्रयास करते देखकर समिति के सदस्य व पालको के मन गदगद हो गये ।साथ ही आगामी वर्षो के लिए अभी से योजना बनाना कार्य में उनके कर्मठता को दर्शाता है । ऐसे शिक्षकों को देखकर लगता है कि पाटन ब्लाक कर्मठ शिक्षकों की कमी नहीं है। पाटन ब्लाक के से शिक्षक है सावनी स्कुल से शिक्षक सुनील कुमार छेदैय्या, केसरा स्कुल से अनकेश्वर महिपाल, शासकीय प्राथमिक शाला सेलुद स्कुल से मिलिन्द चन्द्रा है ।जिन्हे समिति द्वारा गमछा व श्रीफल से सम्मानित भी किया गया।

तेज बारिश के साथ हुई ओलावृष्टि, तापमान में आई गिरावट

कोरबा। लगातार बदल रहे मौसम के रूख के कारण अंचल में परिस्थितियां परिवर्तित हो रही हैं। दोपहर के बाद तापमान में घटत के साथ शाम तक कालचक्र कुछ अलग ही नजर आ रहे हैं। पिछले एक सप्ताह से इस तरह से नजारे जिले में बने हुए हैं। उत्तर पूर्वी तेज हवाओं और तटीय इलाकों में बने सिस्टम के कारण रात में यहां तेज बारिश हुई। जमकर ओले भी गिरे। इसके साथ एक बार फिर तापमान में गिरावट दर्ज हुई है।

पड़ोसी राज्य मध्यप्रदेश में दो दिन पहले बारिश के साथ ओले गिरने की घटनाएं दिन में हुई। बिल्कुल यही स्थिति औद्योगिक जिले में 48 घंटे बाद निर्मित हुई लेकिन रात्रि में। शुक्रवार को दोपहर बाद से ही मौसम ने अंगड़ायी ली। अंतराल के साथ इसमें और ज्यादा बदलाव हुआ। ऐसे में कयास लगाया जाने लगा कि अगले कुछ घंटे दिक्कत भरे हो सकते हैं। मध्य रात्रि से तेज हवाओं के बीच बारिश का सिलसिला शुरू हुआ। कोरबा शहर और उपनगरीय क्षेत्र में बैशाख महीने की यह

सबसे तेज बारिश रिकार्ड की गई। प्रत्यक्षदर्शियों ने महसूस किया कि इससे पहले हवा की रफ्तार भी बहुत ज्यादा थी और इसका रोमांच डरावना था। इसी दौरान गरज चमक के साथ आकाशीय बिजली ने वातावरण को भयभीत किया। कुछ देर बाद ओलावृष्टि का क्रम शुरू हो गया। कहीं चने के आकार के तो कहीं आंवला के बराबर ओले गिरे।

थोड़ी ही देर में सड़कें और जमीनी क्षेत्र ओले से पट गया। रात्रि में जागरूक लोगों ने विशेष दिलचस्पी लेकर ऐसे नजारों को अपने मोबाईल में कैद किया। इस मामले के वीडियो बनाए और फेटो भी ली। सोशल मीडिया प्लेटफार्म पर आज सुबह से सीजन की पहली ओलावृष्टि के ये नजारे छाये हुए हैं। जानकारी मिली है कि कोरबा जिले के बड़े हिस्से में इस घटना ने अपना प्रभाव डाला। पता चला कि किसानों के अलावा अन्य लोगों के द्वारा खेतों और बाडियों में लगायी गई बागवानी फसलों को ओलो ने काफी नुकसान पहुंचाया है। फसलों का क्षेत्र ओला वृष्टि की मार नहीं सह सका और चौपट हो गया। संबंधित लोगों को इन कारणों से काफी नुकसान झेलना पड़ा है। खासतौर पर व्यवसायिक आधार पर सब्जी उत्पादन करने वाले वर्ग को काफी उम्मीदें थी। जानकार बताते है कि ओलावृष्टि आमतौर पर तेज तूफान के साथ होती है। ओलों के निर्माण के लिए आवश्यक बादल क्यूम्यलोनिम्बस बादल हैं। ये बादल सतह से उठने वाली गर्म हवा के साथ लंबवत विकसित होते हैं। यदि सतह पर चलने वाली ठंडी हवा गर्म हवा के एक अन्य द्रव्यमान से मिलती है, तो यह वृद्धि का कारण बनेगी क्योंकि यह कम घनी होती है।

पूर्व सरपंच की दंबगई, पुलिसकर्मी के परिवार का हुक्का-पानी बंद

कबीरधाम। छत्तीसगढ़ के कबीरधाम में इस बार एक पुलिसकर्मी के परिवार का हुक्का-पानी बंद कर दिया गया है। इसके साथ ही गांव में मुनादी कराई गई है कि जो भी इस परिवार से बात करेगा उसे 1051 रुपये का अर्थदंड़ देना होगा। पुलिसकर्मी के परिवार की गलती सिर्फ इतनी है कि उसने शासकीय जमीन पर अवैध कब्जा करने को पूर्व सरपंच के खिलाफ शिकायत की थी। फिलहाल इस बार पुलिस परिवार ने हुक्का-पानी बंद किए जाने को लेकर एसपी कार्यालय में शिकायत दर्ज कराई है। मामला रेंगाखार जंगल थाना क्षेत्र का है।

ना सामान खरीद सकते, न खेत के लिए मजदूर मिल रहे

जानकारी के मुताबिक, ग्राम बम्हनी निवासी चंद्रपाल चौधरी के परिवार का सामाजिक बहिष्कार किया गया है। आरोप है कि गांव में पूर्व सरपंच डाखनसिंह की दबंगई चल रही है। उसी के कहने पर परिवार का हुक्का-पानी बंद है। इसके कारण उनकी गाय को चारवाहा नहीं ले जा रहा है, दूधवाला दूध देने के लिए पहुंच रहा है। यहां तक कृषि कार्य करने के लिए मजदूर भी नहीं मिल रहे है। दुकान से सामान तक देना बंद कर दिया गया है। इसके चलते परिवार काफी डरा हुआ है। परिवार का छोटा बेटा पुलिस कॉन्सटेबल है।

शासकीय नाले की जमीन पर कब्जे का है आरोप

दरअसल, सारा विवाद शासकीय नाले की जमीन पर अवैध कब्जे को लेकर है। बताया जा रहा है कि डाखनसिंह के नाम पर खसरा नंबर 79 की भूमि स्थित है। उनकी भूमि से लगता हुआ शासकीय भूमि (नाला) खसरा नंबर 65 है। आरोप है कि इसी जमीन पर अवैध रूप से कब्जा कर दीवार का निर्माण किया जा रहा है। इसे लेकर डाखन सिंह को मना किया गया, लेकिन वह नहीं माने। इसके बाद दीवार गिर गई। इसका आरोप चौधरी परिवार पर है। उन्हीं ने तहसीलदार से दीवार तोड़कर निर्माण कार्य बंद कराने की शिकायत की थी।

राष्ट्रीय/अंतरराष्ट्रीय
प्रमुख समाचार

कांग्रेस अध्यक्ष पर नरोत्तम मिश्रा का निशाना

जबलपुर। कांग्रेस अध्यक्ष ने कर्नाटक चुनाव में एक सभा को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जहरीला सांप बता दिया। अब इसी को भाजपा ने बड़ा मुद्दा बना लिया है। इन सब के बीच मध्य प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने मल्लिकार्जुन खरगे पर निशाना साधा है। भाजपा नेता ने कहा कि न जाने मल्लिकार्जुन खरगे इतना जहर कहां से लाते हैं। लगता है कि वह 10 जनपथ पर जाकर रिचार्ज करवाते हैं। दरअसल, नरोत्तम मिश्रा ने यह बयान जबलपुर में दिया है। अपने बयान में मिश्रा ने यह भी कहा कि अपने बयानबाजी की वजह से ही राहुल गांधी को आज कोर्ट के चक्कर लगाने पड़ रहे हैं। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि इसी जहर भरी बातों के कारण दिग्विजय सिंह पर आरोप तय हुए है। उन्होंने कहा कि पीएम मोदी को मौत का सौदागर बताने का अंजाम गुजरात में सोनिया गांधी को भुगतना पड़ा और अब खरगे को भी बयान का खमियाजा कर्नाटक के चुनाव परिणाम से भुगतना पड़ेगा।

केजरीवाल के बंगला विवाद पर एलजी ने दिए जांच के आदेश

नई दिल्ली। आम आदमी पार्टी के संयोजक और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के आधिकारिक आवास को लेकर छिड़े विवाद में अब उपराज्यपाल की एंट्री हो गई है। अरविंद केजरीवाल के आवास के रेनोवेशन के दौरान कथित अनियमितताओं को लेकर उपराज्यपाल वीके सक्सेना ने एक रिपोर्ट मांगी है। उपराज्यपाल ने मुख्य सचिव को रिकॉर्ड की जांच करने और पूरी रिपोर्ट 15 दिनों के अंदर पेश करने का आदेश दिया है। उपराज्यपाल के ऑफिस की ओर से जारी किए गए बयान में कहा गया है, दिल्ली एलजी ने मीडिया रिपोर्टों का संज्ञान लिया है जिसमें मुख्यमंत्री आवासा के नवीकरण के दौरान की गई कथित घोर अनियमितताओं पर और मामले की संवेदनशीलता को ध्यान में रखते हुए, मुख्य सचिव को मामले से संबंधित सभी रिकॉर्ड को तुरंत सुरक्षित करने और सुरक्षात्मक में लेने का निर्देश दिया। इसके बाद इस तथ्यात्मक रिपोर्ट को 15 दिनों के भीतर पेश करने का निर्देश भी दिया गया है।

मोदी चाहे जितनी कोशिश कर लें, केजरीवाल का काम नहीं रोक पाएंगे : सिसोदिया

नईदिल्ली। आम आदमी पार्टी के नेता और दिल्ली के पूर्व उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया को प्रवर्तन निदेशालय द्वारा जांच किये जा रहे आबकारी मामले में उनकी न्यायिक हिरासत की समाप्ति पर शनिवार को राउज एवेन्यू कोर्ट ले जाया गया। दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने मामले में आप नेता और दिल्ली के पूर्व उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया की न्यायिक हिरासत 8 मई तक बढ़ा दी है। राउज एवेन्यू कोर्ट से निकलते हुए दिल्ली के पूर्व उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने मीडिया के समक्ष प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि मोदी चाहे जितनी कोशिश कर लें, लेकिन दिल्ली में केजरीवाल जी का काम नहीं रोक पाएंगे। मोदी जितना चाहें साजिश कर लें लेकिन दिल्ली में विकास होकर रहेगा। यहां चर्चा कर दें कि दिल्ली की एक अदालत ने कथित आबकारी नीति घोटाले से संबंधित मनी लॉन्ड्रिंग के एक मामले में मनीष सिसोदिया की जमानत याचिका शुक्रवार को खारिज कर दी थी।

कर्नाटक चुनाव के बाद होगी विपक्षी दलों की बैठक : नीतीश

पटना। विपक्षी एकता की मुहीम के सवाल पर बोलते हुए बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा है कि एक बैठक कर यह निर्णय लिया जाएगा कि किस तरह से विपक्ष को मजबूत किया जाए। यह पूछे जाने पर की आपके तरफ से विपक्षी एकता को बल दिया जा रहा है। अब जबकि लालू यादव भी पटना आ चुके हैं और ममता बनर्जी ने भी कहा था कि पटना से विपक्षी एकता को बल दिया जाए तो इसको लेकर क्या निर्णय लिया गया है? इसपर नीतीश कुमार ने कहा कि इसको लेकर सभी दलों की बैठक की जाएगी। सीएम नीतीश कुमार ने कहा है कि फिलहाल कुछ राज्यों में चुनाव है, इसलिए वहां की पार्टी अभी उस तरफ अपना ध्यान दे रही है। इसके बाद इसको लेकर बैठक होगी। यदि पटना में सभी लोगों की सहमति बनती है तो किसी भी तरह की कोई समस्या नहीं है। उन्होंने कहा कि हम पहले ही बता दिए हैं। हम लोग कोशिश कर रहे हैं, बातचीत हुई है अभी और कुछ लोगों से बातचीत होनी है। इसके बाद तय हो जाएगा।

मुख्तार अंसारी को गैंगस्टर एक्ट में हुई 10 साल की सजा

लखनऊ। माफिया मुख्तार अंसारी पर गैंगस्टर मामले में कोर्ट ने अपना फैसला सुनाया है। कोर्ट ने मुख्तार अंसारी को दस साल की सजा सुनाई है। इसके साथ ही उनपर 5 लाख का जुर्माना भी लगाया गया है। गाजीपुर की एमपी/एमएलए कोर्ट ने 2005 के कृष्णानंद राय अपहरण-हत्या मामले में उन्हें शनिवार को दोषी करार दिया। मुख्तार को 10 साल जेल की सजा सुनाई गई है। उनके बड़े भाई और शहर के बसपा सांसद अफजाल अंसारी को भी दोषी ठहराया गया और चार साल की सजा सुनाई है। अफजाल अंसारी पर एक लाख का जुर्माना भी लगा है। अफजल के लिए फैसला बेहद महत्वपूर्ण है क्योंकि सजा का मतलब लोकसभा सीट हारना है। इससे पहले दिन में अंसारी बंधुओं के खिलाफ अपहरण और हत्या के एक मामले में फैसला सुनाने के लिए गाजीपुर अदालत के बाहर कड़ी सुरक्षा व्यवस्था की गई थी।

इतना टाइम सुशासन में लगाते तो दयनीय स्थिति न होती

कांग्रेस मुझे 91 बार गाली दे चुकी : मोदी

बेंगलुरु। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शनिवार को कर्नाटक में अपनी पहली चुनावी रैली को संबोधित किया। उनकी पहली रैली बीदर के हुमनाबाद में हुई है, जहां उन्हें सुनने के लिए बड़ी संख्या में लोग इकट्ठा हुए। यहां पीएम ने कहा, ये मेरा सौभाग्य है कि इस विधानसभा चुनाव में मेरी शुरुआत बीदर से हो रही है। बीदर का आशीर्वाद मुझे तब भी मिला था जब मैं पीएम पद का उम्मीदवार बना था। आज इतनी बड़ी संख्या में यहां आ कर आपने पूरे देश को संदेश दे दिया है कि- इस बार, भाजपा सरकार। यह चुनाव कर्नाटक को देश में नंबर-1 राज्य बनाने का चुनाव है।

मोदी ने आगे कहा, कर्नाटक का यह चुनाव केवल 5 वर्ष के लिए सरकार बनाने मात्र का नहीं है, यह कर्नाटक को देश में नंबर वन राज्य बनाने का चुनाव है। ये विकसित भारत के लिए कर्नाटक की बड़ी भूमिका तय करने वाला चुनाव है और भारत विकसित तभी होगा जब कर्नाटक का कोना-कोना विकसित होगा।

कांग्रेस ने मुझे गाली देने का काम शुरू किया

पीएम मोदी ने कहा, कांग्रेस हर उस व्यक्ति से नफरत करती है जो सामान्य मानवी की बात करता है, जो उनके भ्रष्टाचार को सामने लाता है, जो उनकी स्वार्थ भरी राजनीति पर प्रहार करता है। इस चुनाव में भी कांग्रेस ने फिर से मुझे गालियां देने का काम शुरू कर दिया है। मैं उनकी गालियों को तोहफा मानता हूं। अब तक मुझे कांग्रेस के लोगों ने 91 बार अलग अलग गालियां दी हैं। इन गालियों के शब्दकोष में टाइम खराब करने की बजाए अगर कांग्रेस ने इतनी मेहनत गुड गवर्नेंस में की होती तो इनकी इतनी दयनीय स्थिति नहीं होती।

कांग्रेस ने कभी बंजारा साथियों की सुध नहीं ली

बीदर में प्रधानमंत्री ने कहा, करोड़ों माताओं-बहनों के बैंक खाते बीजेपी ने खुलवाए, उसमें सरकारी मदद सीधे पहुंचे यह व्यवस्था बीजेपी ने की, बिना गारंटी मुद्रा लोन मिले ये व्यवस्था बीजेपी ने की, मुफ्त राशन की व्यवस्था बीजेपी ने की... हमारे बंजारा साथियों की कांग्रेस ने कभी सुध नहीं ली लेकिन हमने उनको भी विकास से जोड़ा। बीजेपी के इन सेवा कार्यों के बीच कांग्रेस ने सिर्फ समाज को बांटा। जाति, मत, पंथ के आधार पर बंटवारा किया और शासन के नाम पर सिर्फ तुष्टिकरण को बढ़ावा दिया।

जब तक कर्नाटक में कांग्रेस की सरकार रही उसने गरीबों के घर बनाने की रफ्तार धीमी कर दी। डबल इंजन की सरकार बनने के बाद कर्नाटक में गरीबों को 9 लाख के आस पास पक्के घर मिलना तय हुआ। भाजपा ने बीदर में करीब 30 हजार घर बनाए हैं यानी बीदर की 30 हजार बहनों को हमने लखपति दीदी बनाया है।

कर्नाटक में विदेशी निवेश तीन गुना बढ़ा

बीदर में पीएम मोदी चुनावी राज्य कर्नाटक के बीदर जिले में एक रैली को संबोधित करते हुए, प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि कांग्रेस शासन की तुलना में भाजपा शासन के तहत राज्य में विदेशी निवेश तीन गुना बढ़ गया है। कांग्रेस शासन की तुलना में भाजपा शासन में राज्य में विदेशी निवेश तीन गुना बढ़ा है। पीएम नरेंद्र मोदी ने कहा कि प्रदेश में दोगुनी गति से दोहरा विकास हो रहा है। कर्नाटक फिर से भाजपा सरकार के लिए तैयार है। कांग्रेस ने केवल कर्नाटक के किसानों और लोगों से झूठे वादे किए थे। कांग्रेस सरकार के तहत राज्य के किसानों को कोई लाभ नहीं मिला।

छत्तीसगढ़-राजस्थान में कांग्रेस के वादे जमीन पर नहीं उतरे

पीएम ने कहा, कांग्रेस को कभी गरीब की तकलीफ समझ ही नहीं आई, इन्होने कभी गरीबी देखी ही नहीं। कांग्रेस वो दल है जो विकास में भी राजनीति करती है, रोड़े अटकाती है। इन्होंने छत्तीसगढ़ और राजस्थान के किसानों से जो वादे किए वो अभी तक धरती पर उतरे नहीं हैं। कांग्रेस ने इस क्षेत्र के गन्ना किसानों को अपने हाल पर छोड़ दिया था जबकि हम उनकी समस्याओं को प्राथमिकता पर दूर कर रहे हैं। जब हमने पीएम किसान सम्मान निधि शुरू की थी तब कर्नाटक में कांग्रेस-जेडीएस की सरकार थी। इनको किसानों से कितनी नफरत है देखिए कि ये लाभार्थी किसानों की सूची केंद्र सरकार को भेजने में रुकावटें पैदा करते थे। उनको तकलीफ यह थी इसमें बीच में कोई कटकी नहीं थी, पैसा सीधे किसानों के खाते में जा रहा था।

कर्नाटक में डबल इंजन की सरकार बेहद जरूरी

कर्नाटक को देश का नंबर-1 राज्य बनाने के लिए यहां डबल इंजन सरकार का होना बेहद जरूरी है। कांग्रेस की सरकार में हर साल 30 हजार करोड़ रुपये के आसपास विदेशी निवेश कर्नाटक में आता था जबकि बीजेपी की सरकार में अब हर साल करीब 90 हजार करोड़ रुपये का विदेशी निवेश कर्नाटक में आ रहा है। डबल इंजन सरकार का मतलब होता है- डबल बेनिफिट, डबल स्पीड।

चुनाव में कांग्रेस का बुरा होगा हाल

पीएम मोदी ने कहा कि पहले कांग्रेस द्वारा कहा गया कि चौकीदार चोर है। फिर कहा गया कि मोदी चोर है। अब कांग्रेस नेताओं ने कर्नाटक के लिंगायत समुदाय को भी गाली दी है। पीएम मोदी ने कहा कि कांग्रेस वाले जब भी गाली देते हैं तो उनका चुनाव में बुरा हाल होता है। इसके अलावा पीएम मोदी ने कहा कि लोगों ने संविधान के निर्माता बाबासाहेब भीमराव आंबेडकर को भी कांग्रेस के लोगों ने राष्ट्रद्रोही जैसी गाली दी। कांग्रेस के लोग वीर सावरकर को भी गाली देते हैं।

उन्होंने कहा कि जब काग्रेंस द्वारा उनको गाली दी जाती है, तो उन्हें ऐसा लगता है कि जैसी उनकी सावरकर और आंबेडकर जैसे महापुरुषों से तुलना की जा रही है। पीएम मोदी ने कहा कि कर्नाटक की जनता के आशीर्वाद से उन्हें दी जाने वाली गालियां मिट्टी में मिल जाएंगी। पीएम मोदी ने कहा कि कांग्रेसी गाली देते रह जाएंगे। पीएम मोदी ने कर्नाटक की जनता से कांग्रेस को किसी भी सूरत में न जिताने की अपील की है। उन्होंने कहा कि राज्य के लोग इस बार चुनाव में कांग्रेस को जवाब देंगे। पीएम मोदी ने जनता से अपील करते हुए कहा कि बीजेपी को अपना वोट देकर राज्य में पूर्ण बहुमत की सरकार बनाएं।

कांग्रेस की इस तिकड़ी ने बढ़ाई भाजपा की टेंशन

बेंगलुरु। कर्नाटक विधानसभा चुनाव रोचक होता जा रहा है। दक्षिण के अपने एकलौते दुर्ग को बचाए रखने के लिए जहां भाजपा जंग लड़ रही है तो वहीं दूसरी ओर सत्ता में वापसी के लिए कांग्रेस हाथ-पैर मार रही है। इस बार बीजेपी के लिए कर्नाटक में कांग्रेस नेताओं की तिकड़ी चुनौती बन गई है। इस तिकड़ी से बोम्मई और येदियुरप्पा पार नहीं पा रहे हैं। इनमें से पहला नाम कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष डीके शिवकुमार, दूसरा नाम पूर्व मुख्यमंत्री सिद्धारमैया और तीसरा नाम पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे हैं। कांग्रेस एक बार फिर से इसी के सहारे बीजेपी से हाथों से सत्ता छीनने की कोशिश में जुटी है।

संकटमोचन डीके शिवकुमार

कांग्रेस की तरफ से कर्नाटक चुनाव की कमान डीके शिवकुमार संभाल रहे हैं। वह पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष हैं। डीके शिवकुमार राजनीति के मंझे हुए और जोड़तोड़ के खिलाड़ी माने जाते हैं। वह सात बार के विधायक होने के साथ ही राज्य के हाई प्रोफाइल मंत्री भी रहे हैं। इसलिए उन्हें कांग्रेस पार्टी का संकटमोचक भी कहा जाता है। बता दें कि चुनाव में कांग्रेस का सारा दारोमदार डीके शिवकुमार के कंधों पर है। साल 2013 में जब कांग्रेस ने सत्ता में वापसी की थी, तब शिवकुमार प्रदेश अध्यक्ष थे। उनकी अगुवाई में राज्य में पार्टी पूर्ण बहुमत के साथ आई थी। इसके अलावा वह वोक्कालिगा समुदाय से ताल्लुक रखते हैं। सूबे में 11 फीसदी वोक्कलिगा है। जो करीब 48 विधानसभा सीटों पर अपना प्रभाव रखते हैं। हालांकि वोक्कालिगा जेडीएस का वोटबैंक माना जाता है। बता दें कि जेडीएस के संस्थापक देवगौड़ा और एच डी कुमारस्वामी वोक्कालिगा समुदाय से आते हैं। वहीं बीजेपी के पास वोक्कालिगा समुदाय का कोई प्रभावी चेहरा नहीं है। ऐसे में इस बार वोक्कालिगा समुदाय का झुकाव कांग्रेस की ओर देखने को मिल रहा है। यह झुकाव बीजेपी और जेडीएस के लिए चिंता का विषय है।

सिद्धारमैया हैं दमदार चेहरा

सिद्धारमैया का नाम कर्नाटक की सियासत के सबसे प्रभावी चेहरे के तौर पर आता है। उन्होंने अपना सियासी सफर एचडी देवगौड़ा के साथ शुरू किया था। लेकिन जब पार्टी की कमान कुमारस्वामी के हाथों में गई तो वह पार्टी से अलग हो गए और सिद्धारमैया ने कांग्रेस का दामन थाम लिया। सिद्धारमैया कांग्रेस पार्टी का बड़ा ओबीसी चेहरा बन गया। वह कर्नाटक की राजनीति में शून्य से शिखर तक का सफर तय किया है। सिद्धारमैया विधायक, मंत्री, उप मुख्यमंत्री और सीएम भी रहे। कर्नाटक के कुरुबा समुदाय से सिद्धारमैया ताल्लुक रखते हैं। हालांकि अन्य समुदायों पर भी उनकी अच्छी पकड़ है। कर्नाटक में वह ओबीसी का प्रमुख चेहरा माने जाते हैं। वह सीधे तौर पर जनता के संपर्क में रहते हैं। वहीं उन्होंने ऐलान किया है कि यह चुनाव उनका आखिरी चुनाव है। जिसके कारण जनता का झुकाव उनकी ओर अधिक है। अगर भाजपा की बात करें तो पार्टी के पास उनके कद का कोई नेता नहीं है।

मल्लिकार्जुन खड़गे से मिलेगा पार्टी को लाभ

राज्य में कांग्रेस का तीसरा सबसे बड़ा चेहरा मल्लिकार्जुन खड़गे का है, जिनके हाथों वर्तमान में पार्टी की कमान है। खड़गे ने एक सामान्य कार्यकर्ता के तौर पर अपना सियासी सफर शुरू किया था। जिसके बाद आज वह पार्टी की कमान संभाल रहे हैं। उन्होंने अपनी पांच दशकों से अधिक की राजनीतिक करियर में कई उतार चढ़ाव देखे हैं। इस चुनाव में मल्लिकार्जुन ने अपनी पूरी ताकत झोंक रखी है। वह दलित समुदाय से ताल्लुक रखते हैं। राज्य में दलित समुदाय बड़ी ताकत में हैं। ऐसे में खड़गे कांग्रेस के पक्ष में दलित वोटों को जोड़ने का सियासी तानाबना बुन रहे हैं।

खेल
प्रमुख समाचार

विश्व टेस्ट चैंपियनशिप में कोहली कर सकते हैं कप्तानी

नईदिल्ली। भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप 2023 का फाइनल मुकाबला खेला जाना है। दोनों टीमों के बीच यह खिताबी भिड़ंत 7 जून से द ओवल में होगी। इस मुकाबले के लिए दोनों ही टीमों के स्क्वॉड का भी ऐलान कर दिया गया है। इस बीच भारतीय टीम के पूर्व मुख्य कोच रवि शास्त्री ने टीम इंडिया के कप्तान को लेकर बड़ा बयान दिया है। रवि शास्त्री का मानना है कि कप्तान रोहित शर्मा अगर किन्हीं कारणों से उपलब्ध नहीं रहते हैं तो विश्व टेस्ट चैम्पियनशिप फाइनल जैसे बड़े मैचों में विराट कोहली को कप्तानी सौंपी जानी चाहिये।

रवि शास्त्री ने आगे कहा कि भारतीय टीम प्रबंधन को पिछले साल इंग्लैंड दौरे पर स्थगित हुए आखिरी टेस्ट में कप्तानी के लिये कोहली को कहना चाहिये था चूंकि रोहित उस मैच के लिये उपलब्ध नहीं थे। वहीं, ईएसपीएन क्रिकइन्फो से बात करते हुए शास्त्री ने कहा, 'ऐसे बड़े मैच के लिये मैं चाहूंगा कि रोहित फिट रहें क्योंकि वह कप्तान हैं। लेकिन अगर किन्हीं कारणों से वह नहीं खेल पाते हैं तो भारतीय टीम को उस दिशा में सोचना चाहिये।' उनसे पूछा गया था कि रोहित के नहीं खेलने पर क्या कोहली को टीम की कप्तानी करनी चाहिये। शास्त्री ने कहा कि इंग्लैंड के खिलाफ पांचवें टेस्ट के लिये भी ऐसा ही किया जाना चाहिये था। उन्होंने कहा, 'रोहित के चोटिल होने पर मुझे लगा था कि विराट कप्तान होंगे।' उन्होंने कहा, 'अगर मैं कोच होता तो यही सुझाव देता। मुझे यकीन है कि राहुल (द्रविड़) ने भी यही किया होगा। मेरी उससे बात नहीं हुई है । विराट की कप्तानी में भारत ने श्रृंखला में 2-1 की बढत बनाई थी।' फाफ डु प्लेसी के चोटिल होने के कारण कोहली इस समय आईपीएल में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर की कप्तानी भी कर रहे हैं। डु प्लेसी 'इंपैक्ट खिलाड़ी' के तौर पर खेल रहे हैं।

आर्थिक/वाणिज्य/विज्ञान/
प्रमुख समाचार

कोर सेक्टर में सुस्ती, प्रॉडक्शन पांच माह के निचले स्तर पर

नई दिल्ली। ग्लोबल इकॉनमी बढ़ती सुस्ती और डिमांड में कमी का असर भारत की कोर सेक्टर में नजर आने लगा है। यही कारण है कि आठ कोर सेक्टर का उत्पादन मार्च में पांच माह के निचले स्तर पर चला गया है। आठ कोर सेक्टर का उत्पादन मार्च 2023 में मात्र 3.6% की बढ़ोतरी हासिल कर पाया। फरवरी में इसमें 7.2% की तेजी देखने को मिली थी। पिछले साल मार्च में आठ कोर सेक्टर का उत्पादन 4.8% चढ़ा था। पिछला निचला स्तर अक्टूबर 2022 में 0.7% था। एड्वाइट सिक्योरिटीज के विनय अग्रवाल का कहना है कि आठ कोर सेक्टर में नरमी का साफ मतलब है कि मार्केट में बिक्री में सुस्ती आ रही है, इसके चलते उत्पादन कम हो रहा है। चालू वित्त वर्ष में ग्लोबल इकॉनमी में स्लोडाउन बढ़ने की खबरें आ रही है। ऐसे में अब इस बात पर ध्यान देना होगा कि भारत के बाजार में इसका असर कम से कम पड़े।

नई परियोजनाओं पर खर्च होंगे रिकॉर्ड 29 लाख करोड़

नई दिल्ली। देश में वित्त वर्ष 2022-23 में रिकॉर्ड 29 लाख करोड़ रुपये की नई परियोजनाओं की घोषणाएं हुई हैं। 2021-22 में 22 लाख करोड़ की घोषणाएं हुईं थीं। सबसे ज्यादा 12.4 लाख करोड़ की विनिर्माण क्षेत्र में घोषणाएं हुईं हैं। बैंक ऑफ बड़ौदा की रिपोर्ट के अनुसार, 2021-22 में विनिर्माण क्षेत्र में 10.6 लाख करोड़ की घोषणाएं हुईं थीं। सेवा क्षेत्र में (वित्त को छोड़कर) 10.3 लाख करोड़ की घोषणाएं हुईं हैं, जो दोगुना बढ़त है। इलेक्ट्रिसिटी में 6.1 लाख करोड़ की परियोजनाएं घोषित हुईं हैं, जो 2021-22 में 4.9 लाख करोड़ रुपये की थी। सेवा क्षेत्र में केवल परिवहन और सूचना एवं प्रौद्योगिकी परियोजनाओं में बढ़त आई है। परिवहन में घोषित परियोजनाओं का निवेश 3.9 लाख करोड़ से बढ़कर 8.8 लाख करोड़ रुपये हो गया है।

एसबीआई कार्ड्स का शुद्ध लाभ चौथी तिमाही में मामूली वृद्धि

नईदिल्ली। एसबीआई कार्ड्स एंड पेमेंट सर्विसेज लिमिटेड (एसबीआई कार्ड) का शुद्ध लाभ मार्च, 2023 को समाप्त तिमाही में मामूली वृद्धि के साथ 596 करोड़ रुपये रहा। क्रेडिट कार्ड जारी करने वाली इस कंपनी ने पिछले वित्त वर्ष की समान तिमाही में 581 करोड़ रुपये का शुद्ध मुनाफा अर्जित किया था। एसबीआई कार्ड ने शेयर बाजार को दी सूचना में कहा कि वर्ष 2022-23 की जनवरी-मार्च अवधि के दौरान कंपनी की कुल आय एक साल पहले की अवधि के 3,016 करोड़ रुपये के मुकाबले बढ़कर 3,917 करोड़ रुपये हो गई। समीक्षाधीन तिमाही में इसकी ब्याज आय बढ़कर 1,672 करोड़ रुपये हो गई, जो एक साल पहले 1,266 करोड़ रुपये थी। पूरे वित्त वर्ष 2022-23 में, एसबीआई प्रवर्तित इस कार्ड कंपनी का शुद्ध मुनाफा वित्त वर्ष 2021-22 के 1,616 करोड़ रुपये के मुकाबले 40 प्रतिशत बढ़कर 2,258 करोड़ रुपये हो गया।

सेबी ने कार्वी स्टॉक ब्रोकिंग उसके प्रवर्तक पर सात साल का प्रतिबंध लगाया

नईदिल्ली। बाजार नियामक सेबी ने कार्वी स्टॉक ब्रोकिंग लिमिटेड और उसके प्रवर्तक कोमांदुर पार्थसारथी को प्रतिभूति बाजार में हिस्सा लेने से सात साल के लिए प्रतिबंधित करने के साथ उन पर 21 करोड़ रुपये का जुर्माना भी लगाया है। सेबी ने जारी आदेश में कहा कि ग्राहकों की प्रतिभूतियों को गिरवी रखकर जुटाई गई राशि को केएसबीएल ने अपने समूह की फर्मों- कार्वी रियल्टी इंडिया लिमिटेड और कार्वी कैपिटल लिमिटेड में भेज दिया था। कोष को दूसरी फर्मों के पास भेजने का दोषी पाए जाने पर सेबी ने केएसबीएल और पार्थसारथी पर सात साल का प्रतिबंध लगाने का फैसला किया है। इसके अलावा शेयर ब्रोकिंग फर्म पर 13 करोड़ रुपये और उसके प्रवर्तक एवं प्रबंध निदेशक पर आठ करोड़ रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है।

उपभोक्ता धारणा में सुस्ती बरकरार रहने की उम्मीद

महेश व्यास

मार्च 2023 में उपभोक्ता धारणाओं में वृद्धि धीमी हो गई थी। जनवरी और फरवरी के दौरान 4-5 प्रतिशत की वृद्धि दर दर्ज करने के बाद उपभोक्ता धारणाओं में मार्च में 1.2 प्रतिशत की धीमी वृद्धि देखी गई। अप्रैल के पहले तीन हफ्ते के आंकड़ों से पता चलता है कि मार्च की तुलना में उपभोक्ता धारणाओं में 2-3 प्रतिशत अधिक वृद्धि हो सकती है।

23 अप्रैल को 30 दिनों का गतिशील औसत उपभोक्ता धारणा सूचकांक मार्च के स्तर से 2.8 फीसदी अधिक था। हालांकि यह एक अलग सुधार की तरह दिखता है लेकिन जनवरी और फरवरी की तुलना में वृद्धि काफी कम है। हम बाद में देखेंगे कि यह वृद्धि पूरी तरह से आश्वस्त करने वाली नहीं है।

अप्रैल 2022 से मार्च 2023 के दौरान उपभोक्ता धारणाओं में औसत मासिक वृद्धि 2.68 प्रतिशत थी। इस अवधि के दौरान कोई गंभीर झटका नहीं लगा। फिर भी, उपभोक्ता धारणाओं में मासिक बदलाव कुछ हद तक अस्थिर था। यह बदलाव नवंबर के -1.7 प्रतिशत से लेकर सितंबर में 7.1 प्रतिशत तक था। अप्रैल 2023 में अपेक्षित वृद्धि वर्ष 2022-23 में देखी गई और यह औसत मासिक वृद्धि के करीब होगी।

अप्रैल में उपभोक्ता धारणाओं में अपेक्षित वृद्धि से संकेत मिलता है कि उपभोक्ता धारणाओं में कोई तेजी नहीं आई है जैसा कि 2023 की शुरुआत में लग रहा था। सीएमआईई के उपभोक्ता धारणा सूचकांक (आईसीएस) द्वारा मापी गई उपभोक्ता धारणाएं अब भी अपने महामारी पूर्व स्तर से नीचे ही है और यह तर्क दिया जा सकता है कि उपभोक्ता धारणाएं धीमी गति से बढ़ रही हैं। उपभोक्ता धारणाओं में धीमी और अस्थिर

वृद्धि का मतलब है कि आईसीएस में महामारी से पहले के स्तर जितना सुधार होने में अभी कई महीने लगेंगे। मार्च 2023 में आईसीएस 89.18 के स्तर पर था। सितंबर-दिसंबर 2015 में इसका आधार 100 है। फरवरी 2020 में आईसीएस 105.3 के स्तर पर था, लेकिन कोविड-19 प्रतिबंधों ने इसे बुरी तरह पस्त कर दिया। मार्च 2023 का आईसीएस कोविड से पहले के स्तर से 15.3 प्रतिशत कम था। अगर आईसीएस 2.68 प्रतिशत प्रतिमाह की दर से बढ़ता रहा जैसा कि यह पिछले 12 महीनों में औसतन वृद्धि करता रहा है तब उपभोक्ता धारणाएं सितंबर-अक्टूबर 2023 तक कोविड-पूर्व के स्तर पर वापस आ जाएंगी। यह भारत में त्योहारों के मौसम के समय पर होगा। अगर परिवारों को आमदनी में वृद्धि नहीं दिखाई देती है या भविष्य की आमदनी में वृद्धि या उपभोक्ता टिकाऊ वस्तुओं का उपभोग करने का रुझान नहीं समझ आता है तब भी उपभोक्ता धारणाओं में सुधार नहीं देखा जा सकता है।

वस्तु और सेवा प्रदाता चुनावों के दौरान पूंजी बनाते हैं। निश्चित रूप से इससे कुछ लोगों की आमदनी में वृद्धि हो सकती है और टिकाऊ उपभोक्ता सामान खरीदने के उनके रुझान में तेजी देखी जा सकती है। यकीनन, ये मध्यस्थ बड़े निर्वाचन क्षेत्र की तुलना में चुनाव के लाभार्थियों का एक छोटा सा हिस्सा हैं। इसलिए चुनाव केवल मामूली रूप से धारणाओं में सुधार लाने में मददगार हो सकते हैं लेकिन इससे अलनीनो के प्रभावों की भरपाई होने की संभावना नहीं है, यदि प्रभाव उतने ही गंभीर रहते हैं जितना कि उनके होने का खतरा है।

जनवरी और फरवरी 2023 में उपभोक्ता धारणाओं में एक मजबूत बदलाव भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए मजबूत वृद्धि दर्ज करने के लिए महत्वपूर्ण है। आईसीएस में बदलाव से पता चलता है कि परिवारों के पास उपभोक्ता टिकाऊ वस्तुओं जैसी गैर-आवश्यक वस्तुओं पर खर्च करने के लिए क्या कीमत चुकानी होती है। इन पर खर्च करने का निर्णय न केवल आमदनी के प्रभाव को दर्शाता है बल्कि एक अमूर्त विश्वास को भी दर्शाता है कि भविष्य में आमदनी को लेकर भरोसा है और भविष्य में आर्थिक वातावरण निरंतर वृद्धि के अनुकूल है। संकट के समय या चुनाव के समय हस्तांतरण के माध्यम से आमदनी बढ़ाने से धारणाओं में सुधार नहीं हो सकता है।

विपक्षी दलों को आत्मचिंतन करने की जरूरत

विवेकानंद शांडिल

भारतीय जनता पार्टी के स्टार प्रचारकों की सूची में प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी, गृहमंत्री अमित शाह, भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा, रक्षामंत्री राजनाथ सिंह और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जैसे कई कद्दावर नेताओं के नाम शामिल है। कर्नाटक के अलावा, इस वर्ष मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़, तेलंगाना जैसे कई अन्य राज्यों में भी चुनाव होने हैं, जिसे आगामी लोकसभा चुनाव के मद्देनज़र अत्यंत महत्वपूर्ण माना जा रहा है। इन चुनावों से स्पष्ट रूप से हमें लोगों की सोच के बारे में पता चलेगा कि वे वर्ष 2024 में क्या चाहते हैं? हालांकि, वर्तमान समय में विपक्ष की स्थिति को देखकर नहीं लगता है कि आने वाले कई दशकों में देश के केन्द्रीय सत्ता में कोई बदलाव होने वाला है। एक ओर, प्रधानमंत्री मोदी के सतत मार्गदर्शन में आज भारत आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक जैसे तमाम मोर्चों पर विश्व गुरु बनने की ओर अग्रसर है। तो, वहीं दूसरी ओर, कांग्रेस समेत तमाम विपक्षी दल विचारधारा से भटके हुए नज़र आ रहे हैं। स्थिति यह है कि उन्हें अपने अस्तित्व को बचाने के लिए कुछ भी गुरेज़ नहीं है। नि:संदेह किसी भी लोकतांत्रिक व्यवस्था में विपक्ष की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण होती है। वे सत्ता पर नैतिक और राजनीतिक दबाव बनाते हैं, जिससे शासन में पारदर्शिता सुनिश्चित होती है और राष्ट्र के विकास को बढ़ावा मिलता है। इसी वजह से यह अपेक्षा की जाती है कि हमारा विपक्ष गंभीर, ज़िम्मेदार और परिपक्व हो। लेकिन, क्षेत्रीय दलों से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक, विपक्ष का व्यवहार हमें निराश ही करता है। दिनभर प्रधानमंत्री मोदी पर अनावश्यक रूप से निशाना साधने वाले नेताओं को, यदि हम उनके ही पैमाने पर मूल्यांकन करें, तो आप पाएंगे कि जद (यू) या राजद जैसे समाजवादियों का जन्म जिस कांग्रेस और उसकी संस्कृति के विरुद्ध हुआ। आज ये उसी की दहलीज़ पर खड़े हैं और जिस भाजपा की मदद से लालू प्रसाद यादव को पहली बार 10 मार्च, 1990 को बिहार की सत्ता संभालने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। आज उनका पूरा परिवार भाजपा की आलोचना करते नहीं थकता है। ख़ैर, राजद के वैचारिक पतन के बारे में तो हर किसी को पता है। यदि हम बिहार के वर्तमान मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की चर्चा करें, तो बिहार की जनता के साथ सबसे बड़ा विश्वासघात तो उन्होंने ही किया है। गौरतलब है कि बिहार के राजनीतिक परिदृश्य में नीतीश कुमार की छवि ने उस समय रंग भरना शुरू कर दिया था, जब उन्होंने वर्ष 1994 में कुर्मी चेतना मंच से लालू यादव के विरुद्ध हुंकार भरा था। आगे चलकर, उन्होंने लालू यादव के विरुद्ध भ्रष्टाचार की लड़ाई लड़ी। फलस्वरूप, भाजपा की मदद से वे बिहार के मुख्यमंत्री बने और लालू यादव जेल गये। लेकिन, बीते एक दशकों में उन्होंने केवल अपने स्वार्थ के लिए बिहार के हितों का गला घोंट दिया और आज वह राजद के सहयोग से सत्ता में हैं। वहीं, राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में जिस भ्रष्ट सरकार और नेताओं के विरुद्ध आवाज़ उठाकर अरविंद केजरीवाल मुख्यमंत्री बने। आज अपनी पार्टी को विस्तार देने के लिए उनके साथ ही गठबंधन करने जा रहे हैं। दूसरी ओर, कथित रूप से विपक्ष का एक बड़ा चेहरा माने जाने वाली ममता बनर्जी ने सदैव कांग्रेस के विरुद्ध आवाज़ उठाकर सत्ता में बने में सफलता हासिल की है और आज अपने प्रधानमंत्री बनने के ख़्वाब को पूरा करने के लिए, वह उसी से सहयोग पाना चाहती हैं। कुल मिलाकर, यह कहा जा सकता है कि देश के तमाम प्रमुख विपक्षी दल, भाजपा को हराना तो चाहते हैं, लेकिन बीते 9 वर्षों से अब तक उन्हें यह बोध नहीं हुआ है कि वे लोगों के बीच किन मुद्दों के साथ जाएं और संघर्ष करें। वे कभी मोदी सरकार को पूँजीपतियों की सरकार बता रहे हैं, तो कभी दलित और पिछड़ा विरोधी। लेकिन, उन्हें भी पता है कि प्रधानमंत्री मोदी के जन-कल्याणकारी नीतियों से देश के सवा सौ करोड़ लोगों में जो विश्वास पैदा हुआ है, उनके पास इसका कोई तोड़ नहीं है। यदि उन्हें आने वाले चुनावों में वास्तव में कुछ सार्थक करना है, तो धरना-प्रदर्शन वाली राजनीति से ऊपर उठना होगा। उन्हें देश के सामूहिक चेतना में आए बदलाव को समझने का प्रयास करना होगा।

परिवारवाद के दलदल में धंसता कमल

सिद्धार्थ शंकर गौतम

सत्ता प्राप्ति के लिए राजनीतिक दल अपने उन सिद्धांतों से भी किनारा कर लेते हैं जो उनकी पहचान से जुड़े होते हैं और उनके सहारे वे विपक्षी राजनीतिक दलों पर हमलावर होते हैं। दक्षिण के अपने एकमात्र दुर्ग को बचाने की मंशा से भाजपा ने भी ऐसे ही कुछ समझौते किए हैं। यानी जीत की गारंटी बन चुके चुनावी रणनीति के %गुजरात मॉडल% को कर्नाटक में दोहराने से पार्टी ने बचने की कोशिश की है। यही कारण है कि अपने बुजुर्ग नेताओं को टिकट देने के बदले पार्टी ने दो दर्जन से अधिक नेता पुत्र-पुत्रियों व संबंधियों को विधानसभा टिकट दिए हैं। इनमें ऐसे विधायकों, मंत्रियों, सांसदों के नेता पुत्र हैं जिनका बड़ा राजनीतिक रसूख है किन्तु गिरते स्वास्थ्य व बढ़ती आयु ने उनके राजनीतिक कैरियर पर ब्रेक लगा दिए हैं।

देखा जाए तो राजनीति में परिवारवाद से पल्ला झाड़ने की भाजपा नेतृत्व की कोशिशों को कर्नाटक में पलीता लगा दिया गया है। भाजपा संसदीय दल की बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सांसदों से कहा था, अगर विधानसभा चुनाव में आपके बच्चों के टिकट कटे हैं तो उसकी वजह मैं हूं। मेरा मानना है कि वंशवाद लोकतंत्र के लिए सबसे बड़ा खतरा है। परिवारवाद से जातिवाद को बढ़ावा मिलता है। पार्टी में पारिवारिक राजनीति की इजाजत नहीं दी जाएगी। दूसरी पार्टियों की वंशवाद की राजनीति के खिलाफ लड़ाई लड़ी जाएगी।

हालांकि उनके वक्तव्य के बाद कर्नाटक में टिकट वितरण में पूर्व मुख्यमंत्री बीएस येदियुरप्पा के बेटे विजयेंद्र, विधायक आनंद सिंह के बेटे सिद्धार्थ सिंह, पूर्व विधायक उमेश कट्टी के बेटे निखिल कट्टी, पूर्व एमएलसी और मंत्री जनार्दन रेड्डी के भाई जी करुणाकर रेड्डी, पूर्व विधायक चिक्केगौड़ा के पोते एसडी दिलीप कुमार, विधायक ईश्वर खंडरे के चचेरे भाई प्रकाश खंडरे, विधायक जीटी देवगौड़ा के दामाद रामचंद्र गौड़ा, लोकसभा सांसद कराडी संगन्ना की बहू मंजुला अमरेश, पूर्व मंत्री अरविंद लिंबावली की पत्नी मंजुला, वरिष्ठ नेता कट्टा सुब्रमण्य नायडू के बेटे कट्टा जगदीश जैसे पारिवारिक सदस्यों को इस बार विधानसभा चुनाव में कमल खिलाने की जिम्मेदारी दे दी गई है।

अश्विनी संपांगी, सोमन गौड़ा पाटिल, एसडी दिलीप कुमार जैसे कुछ और नाम हैं जिनके परिवार के सदस्य राजनीति में रहे हैं और ये अपनी किस्मत भाजपा से आजमा रहे हैं। भाजपा के इन पारिवारिक उम्मीदवारों पर तंज कसते हुए कांग्रेस ने कड़ी प्रतिक्रिया दी थी जिसका बचाव

करते हुए राज्य के भाजपा नेताओं ने दलील दी थी कि वे जिस परिवारवाद को समाप्त करने की बात करते हैं उसका स्वरूप दूसरा है क्योंकि उनकी पार्टी में एक ही परिवार का परिवारवाद नहीं चलता। तो क्या राजनीति में परिवारवाद की परिभाषा भी भिन्न है?

क्या राजनीति में परिवारवाद एक बुराई है? यह प्रश्न जितना सीधा है इसका उत्तर उतना ही विविधता भरा है। कुछ लोगों के लिए परिवारवाद एक बुराई है तो कुछ के लिए यह मायने ही नहीं रखता क्योंकि यदि उन्हें परिवारवाद से समस्या होती तो वास्तव में वे हर उस उम्मीदवार को चुनाव में हरा देते जिस पर परिवारवाद का ठप्पा है। लोकतंत्र में परिवारवाद का सबसे बड़ा उदाहरण गांधी-नेहरू परिवार रहा है और इसके बाद नंबर आता है उन क्षेत्रीय राजनीतिक दलों का जिनकी स्थापना ही परिवारवाद को %राजनीतिक पोषण% की सोच के कारण हुई है।

बिहार में लालू प्रसाद यादव, उत्तर प्रदेश में मुलायम सिंह यादव, आन्ध्र प्रदेश में चंद्रबाबू नायडू और रेड्डी परिवार, तेलंगाना में केसीआर, महाराष्ट्र में ठाकरे परिवार, तमिलनाडु में करूणानिधि परिवार, उड़ीसा में पटनायक परिवार, हरियाणा में हुड्डा परिवार, पंजाब में बादल परिवार, जम्मू-कश्मीर में अब्दुल्ला और मुफ़्ती परिवार, कर्नाटक में देवगौड़ा परिवार जैसे बड़े पारिवारिक घराने आज भी राज्य की राजनीति में या तो शीर्ष पर हैं अथवा उनकी उपस्थिति मुख्य विपक्षी दल की है।

अर्थात सीधे शब्दों में कहें तो जनता भी परिवारवाद को गलत नहीं मानती क्योंकि ऐसा होता तो इनकी एक पीढ़ी बाद ही राजनीतिक जमीन खिसका दी जाती। किन्तु देखने में आया है कि इनकी तीसरी-चौथी पीढ़ी भी राजनीति में है और जनता का आशीर्वाद भी उसे प्राप्त हो रहा है। कुल मिलाकर लोकतंत्र के सही मायने समझने में यह जनता और समाज की विफलता है।

राजनीति अपने साथ वर्चस्व भी लाती है और जिसने एक बार अपना वर्चस्व बना लिया, फिर जनता के लिए उसके तिलिस्म को तोड़ना कठिन होता जाता है क्योंकि यह तिलिस्म जाति, धर्म, क्षेत्रवाद, भाषावाद से पुष्ट होता है और जनता को इसके जाल में लंबे समय तक रखना आसान होता है। पहली दुनिया से लेकर तीसरी दुनिया के कई देशों की राजनीति में भी परिवारवाद हावी है जिसका अर्थ है कि लोकतंत्र आज भी अपने वास्तविक अर्थ को खोज रहा है।

1999 से 2014 के बीच चुने गए वंशवादी सांसदों में से 31 सांसद भाजपा के थे वहीं कांग्रेस 36 वंशवादी सांसदों को ढो रही थी। 2019 के लोकसभा चुनाव में भाजपा से कुल 22 प्रतिशत सांसद वंशवाद की बेल थे। 1980 में अपनी स्थापना के बाद से लगभग एक दशक तक तो भाजपा में परिवारवाद की राजनीति नगण्य थी किन्तु 1992 के बाद उत्तर भारत में पार्टी के विस्तार में लगे कद्दावर नेताओं के परिवारीजनों ने भी धीरे-धीरे राजनीति का स्वाद चखा और जैसे-जैसे भाजपा बढ़ी, स्थानीय स्तर पर बड़े नेताओं के पुत्र-पुत्रियों ने राजनीति को विरासत समझकर उसमें हस्तक्षेप प्रारंभ किया।

फिर कई राज्यों में भाजपा ने सरकार बनाने के लिए ऐसे क्षेत्रीय दलों से गठबंधन किया जिनकी राजनीति ही वंशवाद पर आधारित थी। जब आप चारों ओर से बुराई से घिरे हों तो आपमें भी उसका अंश आना तय है, उसकी मात्रा कम या अधिक हो सकती है। इसी कारण भाजपा में भी वंशवाद की राजनीति का चलन बढ़ा है। हालांकि यह थोड़ा सुखद है कि तीन-चार पीढ़ियों वाली वंशबेल को राजनीति में लाना अभी भाजपा में अपेक्षाकृत कठिन है अत: नेताओं के पुत्र-पुत्रियों या संबंधियों तक ही परिवारवाद सिमटा हुआ है किन्तु भाजपा में भी परिवारवाद है इसे नकारा नहीं जा सकता।

भाजपा का कर्नाटक मॉडल यदि कामयाब होता है और पार्टी पुन: सत्ता में वापसी करती है तो देश के हृदय मध्य प्रदेश में भी गुजरात मॉडल के स्थान पर कर्नाटक मॉडल लागू करने की मांग उठ सकती है। क्योंकि लम्बे समय से सत्ता पर काबिज भाजपा के वर्तमान विधायकों व मंत्रियों के प्रति जनता में नाराजगी है और वे टिकट कटने की सूरत में अपने सगे-संबंधियों के लिए टिकट की मांग करेंगे।

इसके अलावा कई ऐसे हैवीवेट नेता-मंत्री हैं जिनके पुत्र-पुत्रियों ने स्वयं ही टिकट की दावेदारी शुरू कर दी है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के पुत्र कार्तिकेय सिंह चौहान, केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया के पुत्र महाआर्यमन सिंधिया, केंद्रीय मंत्री नरेन्द्र सिंह तोमर के पुत्र देवेंद्र सिंह तोमर, वरिष्ठ मंत्री गोपाल भार्गव के पुत्र अभिषेक भार्गव, गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा के पुत्र सुकर्ण मिश्रा, मंत्री कमल पटेल के बेटे सुदीप पटेल, मंत्री गोविन्द सिंह राजपूत के बेटे आकाश सिंह राजपूत, मंत्री यशोधरा राजे सिंधिया के पुत्र अक्षय, पूर्व सांसद प्रभात झा के बेटे तुष्मुल झा, पूर्व मंत्री गौरीशंकर बिसेन की पुत्री मौसम बिसेन कई वर्षों से अपनी दावेदारी कर रहे हैं और इस बार यह दावेदारी कईयों की किस्मत चमका सकती है।

27 अप्रैल को ही मध्य प्रदेश के पूर्व वित्त मंत्री जयंत मलैया के पुत्र सिद्धार्थ मलैया की भाजपा में वापसी हुई है जिन्हें उपचुनाव में बगावत और पार्टी विरोधी गतिविधियों के कारण निष्कासित कर दिया गया था। सिद्धार्थ मलैया इस बार टिकट के प्रबल दावेदार माने जा रहे हैं। 2018 में हुए विधानसभा चुनाव में भाजपा ने 230 उम्मीदवारों में से 48 उम्मीदवार ऐसे उतारे थे जिनका परिवार पूर्व से ही राजनीति में स्थापित था जबकि कांग्रेस ने 23 पारिवारिक उम्मीदवारों को चुनाव में उतारा था। वर्तमान में कई नेता पुत्र-पुत्री विधायक हैं और इस बार भी उनका टिकट कटने की संभावना नगण्य है।

भारतीय ज्ञान परंपरा....

शाण्डिल्यापोनषद् (भाग-16)

गतांक से आगे...

मूर्ति का चिन्तन करना सगुण कहलाता है तथा आत्मा के स्वरूप का ध्यान करना निर्गुण कहलाता है।

॥ एकादश: खण्ड: ॥

अब इसके अनन्तर समाधि का वर्णन करते हैं। जीवात्मा एवं परमात्मा की ऐक्यावस्था, (ज्ञान, ज्ञेय तथा ज्ञाता) की त्रिपुटीविहीन, परमानन्द के रूप से युक्त एवं शुद्ध चैतन्यमय अवस्था ही समाधि कहलाती है। तत्पश्चात् अथर्वा मुनि ने कहना प्रारम्भ किया हे शाण्डिल्य ! ब्रह्म, सत्य, विज्ञान एवं अनन्त रूपों में संव्याप्त है।

जिसमें यह सभी कुछ ओत-प्रोत है। जिसमें यह प्रादुर्भूत होता है तथा अस्त भी होता है, उसी तरह से जिसको समझ लेने से यह सभी कुछ समझ लिया जाता है, वह हाथ-पैर से विहीन, नेत्रों से रहित, कार्य विहीन, जिह्वा रहित, शरीर विहीन, स्वीकार न किये जाने योग्य तथा स्पष्ट रूप से बताये न जा सकने योग्य है।

जिसे प्राप्त किये बिना वाणी एवं मन पीछे की ओर वापस हो जाते हैं। जो मात्र ज्ञान से ही पाया जा सकता है, जिससे प्राचीन प्रज्ञा का प्रचार-प्रसार हुआ है, जो अनुपम एवं अद्वितीय है, आकाश के सदृश सर्वत्र व्याप्त रहने वाले, अति सूक्ष्म, निरञ्जन, क्रियाविहीन, एकमात्र सत्य स्वरूप, चेतना से सम्पन्न, आनन्द स्वरूप, एकरस से सम्पन्न, मंगलमय, अत्यन्त शांत एवं अमर है, वही परम अविनाशी ब्रह्म है। वही तुम हो। ज्ञान के जो एक ही देव आत्मा की शक्ति के रूप में प्रमुख, सब प्रकार से ज्ञान सम्पन्न, सर्वेश्वर, समस्त प्राणियों की अन्तरात्मा, सभी प्राणियों में निवास करने वाले, सब प्राणियों में छिपे हुए सभी प्राणियों का मूल उत्पत्ति स्थान, केवल योग के द्वारा ही जाने जा सकने योग्य है, जो विश्व की सृष्टि, पालन एवं विलय स्वयं करता है, वही आत्मा है। तुम आत्मा में ही उन सबको स्थित जानो।

इस प्रकार अथर्वा मुनि से जानकारी प्राप्त करने के पश्चात् महात्मा शाण्डिल्य ने पुन: प्रश्न किया है भगवन्! जो परब्रह्म एकाक्षर, क्रिया विहीन, मङ्गलमय, सत्ता मात्र एवं आत्म स्वरूप है, उससे यह जगत् किस प्रकार से प्रादुर्भूत होता है ? किस प्रकार वह प्रतिष्ठित होता है तथा किस तरह से उसमें विलीन हो जाता है ? मेरी यह शंका दूर करना अत्यन्त आवश्यक है **क्रमश:...**

आयुष्मान भारत दिवस

अनु शर्मा

हर साल 30 अप्रैल को आयुष्मान भारत दिवस के रूप में मनाया जाता है। पूरे देश में यह ग्राम स्वराज अभियान के रूप में भी सेलेब्रेट किया जाता है। इस दिन भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने इस योजना की शुरुआत की थी। आयुष्मान भारत स्कीम को नेशनल हेल्थ प्रोटेक्शन स्कीम के नाम से भी जाना जाता है। यह देश के सभी रिमोट एरियाज में चिकित्सा सुविधा प्रदान करने और देश के प्रत्येक जरूरतमंद नागरिक को स्वास्थ्य सुविधाएं प्रदान करने के अभियान के महत्व को बढ़ावा देने के लिए मनाया जाता है।

आयुष्मान भारत स्कीम की शुरुआत सबसे पहले 2018 में की गई थी। इस प्लान का उद्देश्य सुविधाओं से वंचित लोगों को बेस्ट मेडिकल फैसिलिटीज प्रदान करना है। यही नहीं, बेरोजगारों को रोजगार देने के लिए मोदी ने आयुष्मान मित्रा जॉब की भी शुरुआत की हैं। नेशनल हेल्थ प्रोटेक्शन स्कीम के अंतर्गत 10 करोड़ से अधिक कमजोर और गरीब परिवारों यानी लगभग 50 करोड़ लाभार्थियों को हर साल 5 लाख रुपये तक का स्वास्थ्य कवर प्रदान किया जाता है। यह योजना उन्हें टर्शियरी और सेकेंडरी अस्पताल में भर्ती होने के कवर का लाभ उठाने में मदद करेगी। यह स्कीम राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना और सीनियर सिटीजन हेल्थ इंशोरेंस स्कीम के मिश्रण है।

आयुष्मान भारत स्कीम के फायदे

फाइनेंशियल प्रोटेक्शन- आयुष्मान भारत स्कीम देश के दस करोड़ से अधिक परिवारों को फाइनेंशियल प्रोटेक्शन प्रदान करती है।

कैशलेस और पेपरवर्क के बिना हैल्थकेयर सर्विस- इस स्कीम से जुड़े लोग बिना कैश और पेपरवर्क के देश भर में किसी भी सूचीबद्ध अस्पताल या चिकित्सा केंद्र में स्वास्थ्य सेवाओं का आनंद ले सकते हैं।

गंभीर बीमारियों का उपचार- इस स्कीम में गंभीर बीमारियों जैसे कैंसर, डायबिटीज, हाइपरटेंशन का उपचार कवर होता है। यह उपचार आमतौर पर आर्थिक रूप से कमजोर लोगों के लिए बहुत ही महंगा होता है।

रोजगार के अवसर- आयुष्मान भारत स्कीम ने हेल्थकेयर सर्विसेज की मांग बढ़ी हैं जिससे स्वास्थ्य सेवा क्षेत्र में रोजगार के अवसर पैदा हुए हैं।

अच्छे हेल्थ परिणाम- इस स्कीम ने क्वालिटी स्वास्थ्य सेवाओं तक एक्सेस प्रदान करके देश में आर्थिक रूप से कमजोर लोगों के स्वास्थ्य परिणामों में सुधार किया है।

आयुष्मान भारत पॉलिसी की एलिजिबिलिटी

अनुसूचित जाति और जनजाति के लोग इस पॉलिसी के लाभ पाने के लिए एलिजिबल हैं। जिन परिवारों में 16 से 59 की उम्र का कोई पुरुष नहीं है, वो इस योजना का लाभ ले सकते हैं। परिवार जिनके पास कोई प्रॉपर घर नहीं हैं, वो भी इसमें शामिल हैं। जिन परिवारों में एक या एक से अधिक विकलांग और अक्षम सदस्य है। मजदूर जिनके पास जमीन या घर नहीं है, उन्हें भी इस योजना में शामिल किया गया है। भिखारियों को भी इस पॉलिसी में शामिल किया गया है। इस नीति में आदिम (प्रिमिटिव) जनजातीय समुदायों को भी ड़ाला गया है। ऐसे परिवार जो मेहतर यानी कूड़ा उठाने वाली पृष्ठभूमि से संबंध रखते हैं, वो भी इस योजना का फायदा उठा सकते हैं।

इतना ही नहीं, आयुष्मान भारत स्कीम लाभार्थियों को कोरोना वायरस के उपचार और परीक्षण के लिए फाइनेंशल कवर भी मिलता है। इस इलाज के लिए पेमेंट संबंधित राज्य सरकार द्वारा सरकारी और निजी अस्पतालों में किया जाता है।

एक फोन टैपिंग से पाकिस्तान में उठा तूफान

मरिआना बाबर

भारत और पाकिस्तान में सबकी निगाहें सूडान पर टिकी हैं, जहां गृहयुद्ध जारी है। वहां के नागरिकों को बिजली, भोजन और शुद्ध पेयजल के संकटों का सामना करना पड़ रहा है। कुछ समय पहले यूक्रेन युद्ध के समय भी ठीक ऐसी ही स्थिति थी, जब भारत और पाकिस्तान अपने नागरिकों, विशेषकर छात्रों को युद्ध क्षेत्र से बाहर निकालने की कोशिश कर रहे थे।

उस समय कूटनीतिक प्रयास सफल हुए थे, और रूस ने कुछ दिनों और घंटों के लिए युद्धविराम की घोषणा की थी, ताकि लोग बाहर निकल सकें। हर किसी को यह हमेशा याद रहेगा कि कैसे विभिन्न देश, यहां तक कि जिनके संबंध अच्छे नहीं थे, उन्होंने भी अपने तनाव को भुलाकर एक-दूसरे की मदद की। पाकिस्तान और भारत, दोनों ने एक-दूसरे की, विशेष रूप से छात्रों की मदद की थी।

यूक्रेन और सूडान विश्व की बदलती वास्तविकताओं के केवल दो उदाहरण हैं। अचानक हुए संघर्ष और गृहयुद्ध सभी को हैरान कर रहे हैं और अब यह नया कायदा प्रतीत होता है। इसलिए क्षेत्रीय देशों को एकजुट होकर भविष्य के लिए आकस्मिक योजनाएं बनानी होंगी।

भारत और कुछ अन्य मुल्कों द्वारा पाकिस्तान में होने वाले शिखर सम्मेलन को वीटो करने के बाद सार्क (दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन, दक्षेस) कमोबेश मर चुका है। सार्क सर्वसम्मति से काम करता है और अगर एक देश विरोध करता है एवं उससे दूर रहता है, तो पूरी व्यवस्था ठप हो जाती है। यह कम से कम आपातकालीन स्थितियों के

दौरान क्षेत्रीय देशों के किसी अन्य मंच पर एकजुट होने और इस बात पर सहमत होने का समय है कि युद्ध क्षेत्रों से अपने नागरिकों को निकालने के दौरान वे एक-दूसरे की देखभाल करेंगे। इससे हर देश लाभान्वित होगा। लेकिन इस बीच पाकिस्तान की एक खबर ने सूडान की खबरों को पीछे धकेल दिया है, जिसका मुल्क की न्यायिक एवं राजनीतिक प्रक्रिया पर महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ेगा। भारतीय टीवी शो क्योंकि सास भी कभी बहू थी से पाकिस्तान के भी बहुत से लोग परिचित हैं। लेकिन अभी पाकिस्तान की एक सास प्रसिद्ध हो गई है और सोशल मीडिया पर सार्वजनिक किए गए एक लीक फोन कॉल के चलते लोगों के बीच चर्चित हो गई है।

पिछले एक साल से पाकिस्तान में कोई भी ऐसा नहीं है, जिसका फोन टैप न हुआ हो। हालांकि दुनिया भर में फोन कॉल सरकार और खुफिया एजेंसियों द्वारा टैप किए जाते हैं, लेकिन यह दुर्लभ है कि बाद में इन ऑडियो और वीडियो को ब्लैकमेल और शर्मिंदा करने के लिए सार्वजनिक किया जाता है। प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ, पीटीआई प्रमुख एवं पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान, मरियम नवाज शरीफ, जज, राजनेता और नौकरशाह के भी फोन टैप किए गए हैं। इमरान खान का एक महिला राजनेता के साथ बात करते हुए ऑडियो वास्तव में बहुत ही शर्मनाक है, क्योंकि यह बेहद निजी बातचीत है, लेकिन इसका उनके समर्थकों पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा है।

पाकिस्तान में सिर्फ सशस्त्र बल ही ऐसा संस्थान है, जो सुरक्षित बचा हुआ है और जिसके फोन टैप करके सार्वजनिक नहीं किए गए हैं। इसलिए यहां पूछा जा रहा है कि क्या सशस्त्र बल और उसकी खुफिया एजेंसियां इन ऑडियो और वीडियो संदेशों को टैप कर सार्वजनिक कर रही हैं? यही वजह है कि मौजूदा सरकार के कैबिनेट मंत्रियों ने भी निंदा करते हुए अपनी चिंता जताई है और इन रिकॉर्डिंग के पीछे कौन है-इसकी जांच की मांग की है। आंतरिक मामलों के मंत्री राणा सनाउल्लाह ने हाल ही में पाकिस्तान के मौजूदा प्रधान न्यायाधीश की सास से संबंधित ऑडियो लीक के बारे में कहा है कि ऑडियो देश पर पड़ने वाले प्रभावों से संबंधित है और कुछ केंद्रीय मंत्रियों ने यह भी मांग की कि प्रधान न्यायाधीश इस्तीफा दे दें।

इस बीच, एक ही दिन प्रांतीय और आम चुनाव कराने के संबंध में एक महत्वपूर्ण मामले की सुनवाई तीन सदस्यीय पीठ द्वारा बुधवार को होनी थी। पर आश्चर्यजनक रूप से सुप्रीम कोर्ट ने इसे सूची से निकाल दिया, क्योंकि खबरों में बताया गया कि मुख्य न्यायाधीश की तबीयत ठीक नहीं है और वह बीमार हैं। आमतौर पर मुख्य न्यायाधीश के अनुपलब्ध होने पर उनकी जगह कोई और ले लेता है, लेकिन उन्होंने किसी और को नामित नहीं किया। पत्रकार सिरिल अल्मेडा कहते हैं, रिकॉर्डिंग (चाहे असली हो या नकली), वीडियो की कोई परवाह नहीं करता, यहां तक कि जिनकी रिकॉर्डिंग होती है, वे भी परवाह नहीं करते।

पीपीपी के एक वरिष्ठ सदस्य सीनेटर फरहतुल्ला बाबर ने कहा कि पूछे जाने वाले प्रश्नों के क्रम पर ध्यान दिया जाना चाहिए। सास का ऑडियो टैप असली है या नकली? यदि फर्जी है, तो बात खत्म। यदि वास्तविक है, तो यह निर्णायक घड़ी है। ज्यादा परेशान करने वाली बात क्या है? निजी बातचीत टैप करना या टैप की सामग्री या न्याय के तराजू को झुकाने की इसकी क्षमता? इस हफ्ते यहां ठीक यही हुआ है।

ये कम्बख्त मार्शल लॉ भी नहीं लगता- पाकिस्तान के मौजूदा प्रधान न्यायाधीश अता उमर बांदियाल की सास महजबीं नूर पीटीआई की समर्थक राफिया तारीक से कहती हैं। राफिया तारीक सुप्रीम कोर्ट में इमरान खान का केस लड़ने वाले वकील ख्वाजा तारीक रहीम की पत्नी हैं। महजबीं सैन्य प्रमुख असीम मुनीर के बारे में बात कर रही हैं, जिन्होंने घोषणा कर दी है कि सेना इस मामले में तटस्थ रहेगी और राजनीति में दखल नहीं देगी। दो पत्नियों का फोन पर बात करना और ताजा राजनीतिक मुद्दों पर चर्चा करना कोई बड़ी खबर नहीं है। लेकिन ये दोनों महिलाएं साधारण नहीं हैं, बल्कि सुप्रीम कोर्ट में कुछ बेहद महत्वपूर्ण लोगों की रिश्तेदार हैं। इसकी पृष्ठभूमि में सरकार, संसद और सुप्रीम कोर्ट के बीच चल रही खींचतान है, जहां हर संस्था यह साबित करने की कोशिश कर रही है कि संविधान के तहत उसके पास कुछ अधिकार हैं।

बापू की दिनचर्या

दाँतों और आँतों की सफाई

रात में बापू के बिस्तर के पास पेशाब का पात्र रखा जाता। वे उसका ही उपयोग करते । जोहांसवर्ग में बापू खड़े-खड़े दातुन करते। उन दिनों इस काम में उनको पंद्रह मिनट लगते। वे वहाँ इस अवधि में गीता कंठस्थ करते। बापू की दातुन की विधि का महत्त्व था। फिनिक्स (दक्षिण अफ्रीका) निवास के दिनों में वे प्राय: कहते कि सुबह दातुन करने के साथ ही हमें आध्यात्मिक दातुन करनी चाहिए। मुँह का मैल ज्यों-ज्यों साफ करते जाएँ, त्यों-त्यों मन का मैल भी निकालना चाहिए। उन्होंने अपनी यह आदत बना ली थी कि दातुन के साथ गंभीर चिंतन किया करते। साथ के लोग जब दातुन करते, तब बापू की उपस्थिति के कारण गणशप नहीं कर पाते। वातावरण शांत और गंभीर रहता । बापू अत्यंत गहराई से आत्मचिंतन में लीन दिखाई देते। किसी से कुछ कहना जरूरी होने पर संकेत भर कर ।। वे यथासंभव मौन रहते। उन दिनों प्रात:कालीन प्रार्थना का आरंभ नहीं हुआ था। दातुन के समय का उनका यह चिंतन ही प्रार्थना की आंशिक पूर्ति करता। बापू की दातुन बबूल की होती, जिसका सिरा चीर और कूटकर कूँची की शक्ल में रात में उनके बिस्तर के निकट रख दिया जाता। साथ ही, एक स्टूल पर पानी और लोहे का एक छोटा-सा तसला कुल्ला करने के लिए रहता। बादाम के जले हुए छिलकों तथा नमक को पीसकर बनाये गए मंजन का वे अधिकतर व्यवहार करते। दातुन को चीरकर उससे जीभ साफ करते। वे दान की चीर को फेंकने के बजाय उसे पानी से अच्छी तरह धोकर एक बर्तन में इकट्ठा करते और सूख जाने पर जलाने के लाते। इस प्रकार गंदगी नहीं फैलती और न वह चीर व्यर्थ जाती। काम दंत मुख शुद्धि के बाद रोज बापू गरम पानी में शहद, नीबू का रस, सोडा-बॉय-कार्ब मिलाकर ग्रहण करते। सुबह सवा चार बजे गरम पानी में नींबू का रस मिलाकर पीने की उनकी आदत यरवदा जेल में सन् 1922 में पड़ी। वहाँ वे शहद और गरम पानी भी लेते, नींबू का रस, शहद और गरम पानी- तीनों मिलाकर भी। सन् % 32 यरवदा में सुबह नौ बजे और शाम को छह बजे वे सोडा तथा नींबू लेते। बापू नियमपूर्वक दातुन के तुरंत बाद आध सेर खौलते पानी में शहद और सोडा मिलाकर बहुत चाव से पीते। ऐसा वे मेद-नाश तथा आँतों की शुद्धि के लिए करते ।

संक्षिप्त समाचार

ओम माथुर व अरुण साव रायपुर ग्रामीण के भानसोज़ मंडल में सुनेंगे मोदी जी के मन की बात

रायपुर। भारतीय जनता पार्टी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के %न की बात की 100वीं कड़ी ज़्यादा-से-ज़्यादा लोगों के साथ सुनने का कार्यक्रम बनाया है। ज्ञातव्य है, प्रधानमंत्री श्री मोदी के लोकप्रिय मासिक प्रसारण मन की बात की 100वीं कड़ी का प्रसारण रविवार, 30 अप्रैल की सुबह होगा। इस दृष्टि से भाजपा ने प्रदेशभर में इसके लिए कार्यक्रम प्रभारी तय किए हैं, जो अपने-अपने निर्धारित मंडल व बूथ केन्द्रों पर कम-से-कम 100 लोगों की उपस्थिति सुनिश्चित कर उनके साथ मन की बात सुनेंगे। प्रदेश भाजपा प्रभारी ओम माथुर रायपुर ग्रामीण जिले के भानसोज में इस कार्यक्रम के लिए उपस्थित रहेंगे। उनके साथ प्रदेश अध्यक्ष अरुण साव भी रहेंगे। भाजपा प्रदेश संगठन महामंत्री पवन साय आरंग विधानसभा में, केन्द्रीय राज्य मंत्री रेणुका सिंह रामानुजगंज मंडल, सांसद गोमती साय फरसाबहार मंडल के मंडरबहार, सांसद गुहाराम अजगल्ले डभरा मंडल, सांसद संतोष पाण्डेय डोंगरगाँव मंडल के अर्जुनी, सांसद विजय बघेल पाटन दक्षिण मंडल, सांसद सुनील सोनी रायपुर के लाखेनगर मंडल के सुंदर नगर, सांसद चुन्नीलाल साहू कोमाखान मंडल के ग्राम टेमरी, सांसद मोहन मंडावी काँकेर ग्रामीण मंडल के दशपुर और सांसद डॉ. सरोज पाण्डेय दुर्ग शहर मंडल के कार्यक्रम में उपस्थित रहेंगीं। इसी तरह भाजपा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष व पूर्व मुख्यमंत्री डॉ. रमन सिंह राजनांदगांव ग्रामीण मंडल के ग्राम फरहाद, नेता प्रतिपक्ष नारायण चंदेल नवागढ़ मंडल के ग्राम सेमरा,पूर्व मंत्री बृजमोहन अग्रवाल लाखेनगर मंडल के भाठागाँव, उपस्थित रहकर मन की बात सुनेंगीं।

कांकेर में साथियों की गिरफ्तारी का नक्सलियों ने किया खंडन

कांकेर। जिले में हुई गिरफ्तारी को लेकर नक्सलियों ने खंडन किया है। नक्सलियों ने पर्चे फेंककर कहा है कि उनके साथियों को नहीं पकड़ा गया। पुलिस ने कुछ दिन पहले जिन लोगों को पकड़ा है, उनका हमारे संगठन से कोई लेना-देना नहीं है। आरोप लगाया है कि ग्रामीणों को पकड़कर पुलिस उन्हें नक्सली बता रही है। कि कैंप के आड़ में नक्सली स्थानीय लोगों की गिरफ्तार की जा रही है। जानकारी के मुताबिक, अन्तागढ़ विकासखण्ड में नक्सलियों ने खूड़गांव के पास भारी मात्रा में पर्चे फेककर गिरफ्तारी का खंडन किया है। पर्चे में रावघाट एरिया कमेटी का नाम लिखा हुआ है। पर्चे में आरोप लगाया गया है कि पानीडोबीर गांव के ग्राम सभा सदस्य को नक्सली बताकर गिरफ्तार किया गया है।

बूथ को मजबूत बनाने ली कार्यकर्ताओं की बैठक

कोरबा। युवक कांग्रेस के द्वारा बूथ को मजबूत बनाने के लिए कार्यकर्ताओं की बैठक ली जा रही है। तानाखार विधानसभा क्षेत्र के अध्यक्ष अंकित पाल ने जटगा में कार्यकर्ताओं की बैठक लीए जहां पर बूथ में सूची बनाने कहा गया। रामपुर विधानसभा क्षेत्र के अध्यक्ष शिवम राय ने भी कार्यकर्ताओं की बैठक ली। कटघोरा विधानसभा के अध्यक्ष रहमान खान ने भी कार्यकर्ताओं को सक्रिय कर दिया है। जिला ग्रामीण अध्यक्ष विकास सिंह ने कार्यकर्ताओं से कहा है कि प्रत्येक विधानसभा क्षेत्रों में कार्यकर्ताओं की बैठक लेकर बूथ को मजबूत बनावें। जिला महासचिव मधुसूदन दास व आकाश पटेल के द्वारा भी लगातार सक्रिय होकर कई क्षेत्रों में काम किया जा रहा है।

बागोड़ में विश्व हिन्दू परिषद बजरंगदल ग्राम समिति का किया गया गठन

दसपुर। विश्व हिन्दू परिषद बजरंग दल ग्राम बागोड़ में ग्राम समिति का गठन समस्त ग्राम वासी युवा साथियों के सर्व सम्मति से किया गया। बजरंगी साथियों में ग्राम समिति गठन को लेकर ग्राम में धार्मिक कार्य, गांव में समरसता, रक्त दान, गौ तस्करी को लेकर सशक्त ठोस निर्णय लिया गया। नवीन कार्यकारणी संरक्षक सहदेव टाडिया, हरि राम कोर्राम, प्रभु राम कुंजाम, अध्यक्ष टाइसन नेताम, कार्यकारी विमल कोर्राम, उपाध्यक्ष लव्य जैन, मंत्री विश्व जीत जैन, सह मंत्री टाकेश नेताम, संयोजक नीतिन टाडिया, सह संयोजक ईश्वर यादव, सह संयोजक डोमेंद्र कोरेटी, सत्संग प्रमुख राजू निषाद, गौ रक्षा प्रमुख समीर नेताम, सुरक्षा प्रमुख शिव चरण ध्रुव, महाविधालय प्रमुख चिरंजीव कोर्राम, मठ मंदिर प्रमुख प्रियांशु ठाकुर, नवीन दायित्व की बधाई एवं शुभकामनाएं देते हुए विभाग मंत्री अखिलेश चंद्रोल, विभाग सह संयोजक अखिलेश मिश्रा, जिला अर्चक पुरोहित नोवेंद्र साहू, ग्राम समिति की घोषणा जिला मंत्री भावेश आरदे के द्वारा किया गया।

24 घंटे में 369 कोरोना मरीज मिले, तीन लोगों ने तोड़ा दम

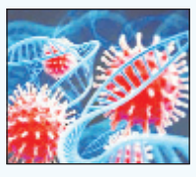

रायपुर। छत्तीसगढ़ में एक फिर कोरोना पैर पसारता नजर आ रहा है।

लगातार कोरोना में बढ़ोतरी देखी जा रही है। पिछले 24 घंटे में प्रदेश में 369 कोरोना मरीज मिले हैं। वहीं 4,967 लोगों की सैंपल जांच हुई है। कोरोना से तीन लोगों ने दम तोड दिया है। आज सबसे ज्यादा धमतरी में 35 मरीज मिले हैं। इसके अलावा रायपुर में 34, दुर्ग में 29, राजनांदगांव में 25, बालोद में 16, बेमेतरा में 13, बलौदाबाजार में 17, महासमुंद में 10, बिलासपुर में 25, जीपीएम में 30, रायगढ में 24, सरगुजा में 21, कांकेर में 24 संक्रमित मिले हैं।

मुख्यमंत्री को फ्रांस की यूनिवर्सिटी ने डॉक्टरेट की उपाधि से नवाजा

जिन्होंने अपने श्रम से छत्तीसगढ़ को खड़ा किया यह सम्मान उन सभी का : मुख्यमंत्री

रायपुर। मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल को विश्वप्रसिद्ध सोरबोन यूनिवर्सिटी द्वारा छत्तीसगढ़ की ग्रामीण अर्थव्यवस्था को सीमित एवं स्थानीय संसाधनों की उपयोगिता के साथ आगे बढ़ाने की विशिष्ट पहल के लिए डॉक्टरेट की उपाधि से नवाजा गया। मुख्यमंत्री श्री बघेल आज श्री अरोबिंदो फाउंडेशन द्वारा राजधानी रायपुर स्थित होटल सायाजी में आयोजित सोरबोन यूनिवर्सिटी ऑफ पेरिस, फ्रांस के कार्यक्रम ग्लोबल अवाड्र्स 2023 में शामिल हुए। इस अवसर पर इसरो के पूर्व वैज्ञानिक सुरेश कुमार, सोरबोन यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर डॉ. विवेक, श्री अरोबिंदो योग एवं नॉलेज फाउंडेशन के डायरेक्टर डॉ. समरेन्द्र घोष, डॉ. बी.के. स्थापक, डॉ. संदीप मारवाह, डॉ. विनय अग्रवाल भी उपस्थित रहे। मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल की धर्मपत्नी श्रीमती मुक्तेश्वरी बघेल एवं उनके परिवार के लोग भी इस कार्यक्रम में शामिल हुए।

कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री श्री बघेल ने कहा कि फ्रांस की प्रतिष्ठित सोरबोन यूनिर्विसिटी ने छत्तीसगढ़ शासन के विकास कार्यक्रमों को सराहा है और मुझे आज डॉक्टरेट की मानद उपाधि से नवाजा है, इसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद। जब काम करना शुरू किया तो बस ये चाह थी कि अच्छा काम करते रहना है। काम करते गए और रास्ता निकलता गया। ये उपाधि जरूर मुझे मिली है लेकिन इसके पीछे योगदान मेरे परिवार वालों का है। जनप्रतिनिधियों का है अधिकारी-कर्मचारियों का है। यह सम्मान छत्तीसगढ़ के सभी मेहनतकश लोगों का सम्मान है जिन्होंने अपने श्रम से छत्तीसगढ़ को खड़ा किया।

मुख्यमंत्री ने आगे कहा कि आज मेरा परिवार भी साथ है। सबसे अच्छी बात है कि मेरा पोता भी साथ है। मेरे घर में एक किताब विनोबा जी की है। उसमें उन्होंने लिखा है कि भारत में महात्मा गांधी, रविन्द्र नाथ, रामकृष्ण परमहंस जैसी विभूति रही हैं और उनका योगदान हमारी मनीषा को बनाने में है। बिना अस्त्र के लड़ाई की कल्पना संभव है क्या, महात्मा गांधी ने इसे साकार किया। अरोबिंदो के योगदान को याद करते हुए उन्होंने कहा कि जब आप निर्लिप्त भाव से कर्म करेंगे तो द्वेष रहित होकर काम करेंगे। जो लोग नैतिकता को प्रधानता देते हैं। वे धन से दूर होते हैं। श्री माँ ने कहा कि नैतिक लोगों को धन से दूर नहीं होना चाहिए। उनके हाथ में धन होगा तो वे सार्थक उपयोग करेंगे।

मुख्यमंत्री श्री बघेल ने कहा छत्तीसगढ़ भौगोलिक रूप से समृद्ध प्रदेश से हैं। हमारे पास जंगल है। हिमालय के बाद सबसे अधिक नाले हमारे यहां हैं। हमारे यहां खनिज संसाधन पर्याप्त है। दुनिया भर में बैटरी गाड़ी की डिमांड हो रही है और हमारे यहां लिथियम है। आरबीआई के सर्वे के मुताबिक हमारे यहां गरीबी रेखा के नीचे बड़ी आबादी है। उद्योग भी है फिर भी गरीबी है। देश के आकांक्षी जिलों में 10 हमारे यहां है, दंतेवाड़ा और कोरबा में प्लांट भी हैं फिर भी इन जिलों में गरीबी है। यह सब देखते हुए एक नए समाधान की दिशा में काम करने की जरूरत थी। इन संसाधनों का प्रभावी उपयोग जरूरी था और हम सबने इसके लिए नीति बनाई। केवल उद्योग धंधों को बढ़ाने से बात नहीं बनती इसलिए हमने प्रकृति को सहेजते हुए विकास कार्य करने का निश्चय किया। मुख्यमंत्री श्री बघेल ने कहा 13 हजार नाले हमने ट्रीट किये लेकिन एक इंच जमीन भी नहीं डूबी, यह नवाचार है। एक-एक बूंद बचा भी ली और किसानों को कष्ट भी नहीं हुआ। जमीन की हमने डिटेल स्टडी की। 13 प्रकार के डिटेल लिए। वाटर रिचार्जिंग काम किया। कहीं भी स्टॉप डैम नहीं बनाया न ही सैंडी साइल में काम किया, क्योंकि इसका कोई लाभ नहीं होता। सही जगह पर नरवा योजना लाने से लाभ यह हुआ कि 7 सेमी से 70 सेमी तक जल स्तर बढ़ गया। गौठान के माध्यम से डेढ़ लाख हेक्टेयर जमीन हमने ग्रामीण विकास के लिए आरक्षित कर ली। पशुधन को गौठान से जोड़ा। वहां चारे की व्यवस्था की। कोरोना के 2 साल कठिन रहे, फिर भी गौठान व्यवस्थित हो गए। गोधन न्याय योजना से सबसे ज्यादा उन लोगों को लाभ हुआ जो गरीबी रेखा के नीचे थे। उनकी आय की निश्चित व्यवस्था हो गई। मुख्यमंत्री ने कहा कि हमने 50 यूनिट स्थापित कर 50 हजार लीटर गोबर पेंट बनाये हैं। शासकीय भवनों में पुताई इससे ही हो रही है। जगदलपुर में गोबर से हम बिजली बना रहे हैं। हम कार्बन उत्सर्जन नहीं कर रहे, ग्लोबल वार्मिंग से लडने् के लिए कार्य कर रहे हैं। जो प्रकृति से लिया है वही प्रकृति को लौटा रहे हैं यही तो हमारे वेदों का संदेश है।

एक हजार से ज्यादा स्वास्थ्य कर्मी हड़ताल पर

- **चार दिन से ओपीडी बंद, डॉक्टर-टेक्नीशियन इसमें शामिल**

दंतेवाड़ा। छत्तीसगढ़ के दंतेवाड़ा जिले में एक हजार से ज्यादा स्वास्थ्य कर्मचारी हड़ताल पर चले गए हैं। इसके चलते स्वास्थ्य सेवाएं चरमरा गई हैं। चार दिन से ओपीडी सेवाएं बाधित हैं। शनिवार से आईपीडी सेवा भी बंद कर दी गई है। इस हड़ताल में डॉक्टरों से लेकर टेक्नीशियन और अन्य मेडिकल स्टाफ शामिल है। यह सभी लोग कोरोना भत्ता दिए जाने की मांग को लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं।

जिले में पदस्थ स्वास्थ्यकर्मियों ने 26 अप्रैल से शासन-प्रशासन के खिलाफ मोर्चा खोल रखा है। इसके कारण जिला अस्पताल समेत जिले के पांच सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों, 13 प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र और 76 उप स्वास्थ्य केंद्रों में स्वास्थ्य सेवाएं प्रभावित हुई हैं। इन चिकित्सालयों में ओपीडी भी बंद है। इसके कारण मरीज भटक रहे हैं। सबसे ज्यादा दिक्कत दूर-दराज से आने वाले ग्रामीण क्षेत्र के मरीजों को हो रही है।

स्वास्थ्यकर्मियों का कहना है कि कोरोना काल में जिले के एक हजार से ज्यादा कर्मचारियों ने अपनी जान को जोखिम डालकर सेवाएं दी हैं, लेकिन कोरोना भत्ता केवल 70 से 80 लोगों को ही दिया गया है। इसे लेकर कर्मचारियों में नाराजगी है। अपनी इस मांग को लेकर पिछले दो-तीन साल से संघर्षरत हैं। अपनी इस एक सूत्रीय मांग को लेकर संयुक्त संगठन के बैनर तले जिलेभर के स्वास्थ्यकर्मियों ने आंदोलन की राह पकड़ी है।

स्वास्थ्यकर्मियों की इस हड़ताल में डॉक्टर, पैरामेडिकल स्टाफ, एनएचएम और फील्ड का समस्त स्टाफ शामिल है। अस्पतालों में ओपीडी बंद होने से मरीज हलाकान हो रहे हैं। दूसरी ओर अति आवश्यक सेवाओं के बाधित होने के बावजूद अभी तक हड़ताल को खत्म करवाने की कोई ठोस पहल नहीं की जा रही है। जबकि छुट्टी के दिनों में भी ओपीडी बंद नहीं करने के निर्देश हैं।

10 हजार स्थानों पर 10 लाख से अधिक लोग सुनेंगे पीएम मोदी के मन की बात

रायपुर। छत्तीसगढ़ में 10 हजार स्थानों पर 10 लाख से अधिक लोग रेडियो पर प्रसारित होने वाले पीएम मोदी के %मन की बात% का 100वां एपिसोड सुनेंगे। इसे लेकर बीजेपी छत्तीसगढ़ ने खास तैयारी की है। समाजसेवी, चिंतकों, डॉक्टर्स, वैज्ञानिक, व्यापारी समेत सभी वर्ग के लिए बैठने के पूरी व्यवस्था की है। ये बातें छत्तीसगढ़ बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष अरुण साव ने आज बीजेपी कार्यालय एकात्म परिसर में आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में कही।

उन्होंने कहा कि पीएम मोदी के मन की बात कार्यक्रम काफी लोकप्रिय है। पीएम इस कार्यक्रम में हर मुद्दों को उठाते हैं। मन की बात से देश को कई उपलब्धि मिली है। लोगों को रोजगार मिला है। मन की बात को अब तक 100 करोड़ लोग देख चुके हैं। मन की बात से लोगों के व्यवहार में बदलाव आया है। कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि कांग्रेस ने मन की बात नहीं सुनी, इसलिए वह विपक्ष में बैठ रही है। पीएम मोदी लोगों के मन की बात सुन रहे हैं। आरक्षण के सवाल पर कहा कि कांग्रेस आरक्षण नहीं देना चाहती है। हमने 32 प्रतिशत आरक्षण दिया था।

'मन की बात' देश में आकाशवाणी व अन्य माध्यमों से प्रसारित किया जाने वाला लोकप्रिय कार्यक्रम है, जिसके माध्यम से भारत के प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी देश जी जनता से संवाद करते हैं। इस कार्यक्रम का पहला प्रसारण 3 अक्तूबर 2014 को किया गया। यह कार्यक्रम 52 भाषाओं एवं बोलियों जिनमें 11 विदेशी भाषाएं शामिल हैं, में प्रसारित होता हैं। यह कार्यक्रम इतना लोकप्रिय हैं कि 27 जनवरी 2015 में अमेरिका के तत्कालीन राष्ट्रपति बराक ओबामा ने भी प्रधानमंत्री के साथ इस कार्यक्रम में भाग लिया और भारत की जनता के पत्रों के उत्तर दिए।

7 मई तक अग्रसेन भवन जवाहर नगर में समर कैंप का आयोजन

रायपुर। रामसागरपारा - जवाहर नगर अग्रवाल मोहल्ला समिति द्वारा 30 अप्रैल से 7 मई 2023 तक समर कैंप-2023 का आयोजन श्री अग्रसेन भवन जवाहर नगर रायपुर में किया गया है। इस समर कैंप में 3 वर्ष से 12 वर्ष के बच्चे भाग ले सकते हैं।

संयोजक आयुष अग्रवाल ने बताया कि समर कैंप में भाग लेने वाले बच्चो के लिए डाँस, चित्रकला एवं हैंडराइटिंग का प्रशिक्षण 30 अप्रैल से 7 मई तक रोजाना शाम 4 बजे से 6 बजे तक दिया गया। प्रशिक्षण के बाद शाम को 6 बजे से 7 बजे तक 12 वर्ष से अधिक ब्च्चों के लिए फ्री वर्कशॉप का भी आयोजन किया गया है। इस समर कैंप में अग्रवाल बंधुओं के बच्चे भी शामिल होंगे। है। समर कैंप में भाग लेने के लिए बड़ी संख्या में रायपुर के अग्रबन्धु अपने बच्चो का और स्वयं का रजिस्ट्रेशन करवा रहे है।

प्रचार प्रसार प्रमुख आयुष मुरारका ने बताया कि इस समर कैम्प में बच्चों के साथ - साथ उनके अभिभावकों के लिए भी फ्री वर्कशॉप का आयोजन किया गया है। उन्होंने कहा कि 30 अप्रैल को राजेश लोइया (खगोल विज्ञान विशेषज्ञ) स्टारगेज़िंग और डीप स्पेस व्यूइंग टेलीस्कोप का उपयोग करना सिखाएंगे। 1 मई को टोकरी और गुलदस्ता सजावट श्रीमती रंजीता अग्रवाल (लोटस आर्ट), 2 मई सही खाएं और वजन कम करें - डॉ. भावना रूंगटा, 3 मई को मॉकटेल (मेकिंग एंड प्रेजेंटेशन) श्रीमती प्रज्ञा राठी, 4 मई पब्लिक स्पीकिंग स्किल्स एंड डायस प्रबंधन श्रीमती स्मिता जैन, 5 मई को मोबाइल फोटोग्राफी और डीएसएल कैमरा सेटिंग्स की मूल बातें - अमित चौहान (द फोटो स्टोरी), 6 मई को सोशल मीडिया के माध्यम से अपना व्यवसाय बढ़ाएँ - बेसिक टू प्रो बाय- श्री रोहित अग्रवाल (रायपुर फूड ब्योरा) तथा 07 मई रविवार को खेल और हौसी के बाद सम्मान समारोह का आयोजन किया गया है।

ऊंचाई से गिरे फोरमैन के परिवार जन धरने पर बैठे

बिलासपुर। उद्योगों में सुरक्षा मापदंडों को दरकिनार करने का खामियाजा वहां कार्यरत कर्मचारियों को अपनी जान अथवा जीवनभर की अपंगता ओढ़कर भुगतना पड़ता। ऐसा ही एक हादसा शुक्रवार को हुआ जिसमें कार्य के दौरान उपस्थित फोरमैन ऊंचाई से नीचे गिर गया और अस्पताल पहुंचते तक उसने दम तोड दिया। इस घटना के बाद फोरमैन की पत्नी अपने दो बच्चों को लेकर मुआवजे तथा नौकरी की मांग को लेकर मरच्यूरी के बाहर धरने पर बैठ गई। प्राप्त समाचारों के अनुसार यह हादसा शुक्रवार का घुट्कु स्थित फील कोल कंपनी का है । जहां एक सप्ताह पूर्व ही अपनी नौकरी की शुरूआत फोरमैन से करने वाला छोटी कोनी निवासी 42 वर्षीय शत्रुघ्न चौबे को सुरक्षा खामियों के चलते इस हादसे में अपनी जान गंवानी पड़ी । औद्योगिक दुर्घटना में श्रमिक की मौत के बाद हंगामा मचा हुआ है। परिजन सिम्स मरचुरी में धरने पर बैठ गए, जिनके द्वारा कंपनी के मालिक को मौके पर बुलाया जा रहा है। परिजन 25 लाख रुपये मुआवजा और प्रतिमाह वेतन देने की मांग पर अड़े हुए हैं। मांग पूरी ना होने पर उन्होंने शव ले जाने से ही मना कर दिया है।

अमन सिंह की याचिका पर सुनवाई से सुप्रीम कोर्ट का इंकार

नई दिल्ली/रायपुर। राहत के सांस की आस लेकर सर्वोच्च न्यायालय की शरण लेने वाले छत्तीसगढ़ के तत्कालीन मुख्यमंत्री रमन सिंह के पूर्व प्रमुख सचिव अमन कुमार सिंह और उनकी पत्नी को जोरदार झटका लगा जब उनकी ओर से दायर याचिका पर न्यायालय की पीठ ने सुनवाई करने से इनकार कर दिया दिया। याचिका में पूर्व अधिकारी खिलाफ आय से अधिक संपत्ति के मामले को सीबीआई को हस्तांतरित करने का अनुरोध किया गया था।

मुख्य न्यायाधीश डी वाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली पीठ ने अपने फैसले में कहा कि केस ट्रांसफर करने के लिहाज से उपयुक्त मामला नहीं है। पीठ के सदस्य न्यायमूर्ति पीएस नरसिम्हा ने कहा, हम देख रहे हैं कि दिन प्रतिदिन राजनीति किसी न किसी रूप में अदालत में लाई जाती है। ऐसा नहीं है कि हम देख नहीं सकते और समझ नहीं सकते। इस मामले में आप के पास अपने उपाय हैं।

अमन कुमार सिंह की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता ए सुंदरम ने कहा कि राज्य के अधिकारियों द्वारा दंपति के जीवन को नरक बना दिया गया है। और खुद मुख्यमंत्री ने लिखा है कि मामले की जांच राज्य पुलिस की आर्थिक अपराध शाखा द्वारा की जानी चाहिए। वहीं अधिकारी ने कोर्ट में कहा, मेरा उत्पीडन् किया जा रहा है। कथक नृत्यांगना मेरी पत्नी को भी उन लोगों ने प्रताड़ित करना शुरू कर दिया है। अब कोई भी उनके साथ काम नहीं करना चाहता। प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने हमें दस्तावेज दिखाए जिसमें राज्य सरकार के अधिकारियों के साथ व्हाट्सऐप चैट का ब्योरा था कि कैसे उन्होंने हमारे लिए मुश्किलें खड़ी कर दी हैं। वरिष्ठ अधिवक्ता महेश जेठमलानी ने सिंह दंपति की ओर से कहा कि उनके खिलाफ अतार्किक जांच जारी है। लेकिन छत्तीसगढ़ सरकार का प्रतिनिधित्व कर रहे वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल और वकील सुमीर सोढ़ी ने आरोपों को दुर्भावनापूर्ण बताया। दंपति को झटका देते हुए शीर्ष अदालत ने इसके पहले भी छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय के उस फैसले को दरकिनार कर दिया था जिसमें उनके खिलाफ प्राथमिकी को रद्द किया गया था। भारतीय राजस्व सेवा के पूर्व अधिकारी सिंह छत्तीसगढ़ में रमन सिंह के नेतृत्व वाली भाजपा सरकार में एक शक्तिशाली नौकरशाह थे। वह नवंबर 2022 में कॉरपोरेट मामलों के प्रमुख के रूप में अडानी समूह में शामिल हो गए हैं।

श्रमिकों और किसानों का बढ़ा मान, बोरे बासी को मिली वैश्विक पहचान

डॉ. दानेश्वरी सम्भाकर

खानपान और रहन सहन संस्कृति से जुड़ा मुद्दा है। छत्तीसगढ़ में कहावत है कि जैसे खाए अन्न वैसा होय मन। यह कहावत बिलकुल छत्तीसगढ़ में सही उतरती है। बोरे-बासी एक सरल और सहज भोजन है। वैसे ही छत्तीसगढ़ के लोग भी सीधे-साधे लोग हैं, इसलिए कहा जाता है कि छत्तीसगढिया सबले बढिया।

मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल ने छत्तीसगढ़ के सीधे साधे श्रमिकों और किसानों का मान बढ़ाने के लिए मजदूर दिवस के दिन लोगों से बोरे-बासी खाने की अपील की है। यह अपील लोगों को भावनात्मक और सांस्कृतिक रूप से जोडने् का भी काम कर रही है। राज्य में छत्तीसगढ़ के सांस्कृतिक वैभव को पिछले चार सालों में नया क्षितिज मिला है। राज्य में मनाए जाने वाले ठेठ छत्तीसगढिया त्योहारों का मान बढ़ा है। मुख्यमंत्री निवास में तीजा, पोरा हरेली त्योहारों को मनाए जाने से लोगों में गर्व की अनुभूति हुई है। मुख्यमंत्री ने इसी कड़ी में एक अनूठी पहल शुरू की है उन्होंने कहा है कि किसानों और श्रमिकों का मान बढ़ाने के लिए बोरे बासी तिहार मनाएं। मजदूर दिवस के दिन अमीर गरीब सभी लोग मजदूरों के पसंदीदा भोजन बोरे बासी खाकर लोगों में आपसी समरसता और भाईचारे का वातावरण बनाए। यह तिहार पिछले वर्ष से शुरू किया गया है। इसकी चर्चा पूरी दुनिया में हुई। अमेरिका ब्रिटेन और लंदन में रहने वाले लोगों ने बोरे-बासी खाकर अपनी मातृभूमि को याद किया। छत्तीसगढ़ के रेस्टोरेंट और होटलों के मेन्यू में भी बोरे बासी को शामिल किया गया है।

मजदूर दिवस

छत्तीसगढ़ के प्रसिद्ध बोरे बासी का शोध अमेरिका में भी किया जा चुका है। वहां इसका अंग्रेजी नाम होल नाइट वाटर सोकिंग राइस रखा है। शोध में यह पाया गया है कि बोरे बासी में ताजा बने चावल (भात) की अपेक्षा इसमें करीब 60 फीसदी कैलोरी ज्यादा होती है। इसके अलावा कई शोधों में यह पाया गया है कि बोरे बासी में विटामिन बी 12 की प्रचुर मात्रा के साथ आयरन, पोटेशियम, कैल्शियम भी भरपूर होती है। बोरे बासी ब्लडप्रेशर और हाइपरटेंशन को नियंत्रित करने का भी काम करता है।

चिलचिलाती धूप और गर्मी में जब छत्तीसगढ़ का मेहनतकश श्रमिक और किसान खाने के लिए गमछा बिछाकर अपना डिब्बा खोलता है, तो उसमें पताल चटनी, गोंदली के साथ बोरे बासी जरुर देखने को मिलता है। पोषक तत्वों से भरपूर इस बोरे बासी से वैसे तो लोग परीचित थे पर इसे वैश्विक स्तर पर नई पहचान दिलाने की अहम भूमिका छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल ने निभाई है। उन्होंने धमतरी जिले के कुरूद विधानसभा क्षेत्र में आयोजित भेंट मुलाकात कार्यक्रम में सभी श्रमिकों को रायपुर में आयोजित श्रम सम्मेलन के लिए न्यौता भी दिया है।

बासी के साथ आम तौर पर भाजी खाया जाता है। पोषक मूल्यों के लिहाज से भाजी में लौह तत्व प्रचुर मात्रा में विद्यमान रहते हैं। इसके अलावा बासी के साथ दही या मही सेवन किया जाता है। जिसमें बड़ी मात्रा में कैल्शियम रहता है। इसके सेवन के फायदों को देखते हुए धीरे-धीरे ये देश-विदेश में भी लोकप्रिय हो रहा है। बच्चों से लेकर बड़े बुजुर्गों भी इसे बड़े चाव से खाना पंसद करते हैं। बोरे-बासी यहां की जीवनशैली का एक अहम हिस्सा है।

छत्तीसगढ़ की संस्कृति और लोक परंपराओं, तीज त्योहारों को बढ़ावा देने के लिए पिछले चार सालों में अनेक कदम उठाए गए हैं। मुख्यमंत्री निवास में तीजा, पोरा, हरेली, जैसे अनेक लोकप्रिय त्योहारों को मनाने की शुरूआत की इससे लोगों में अपनी संस्कृति के प्रति गर्व का भाव जगा। इसके साथ ही स्थानीय तीज त्योहारों पर शासकीय अवकाश भी घोषित किए गए। पारंपरिक खानपान को बढ़ावा देने के लिए सभी जिलों में गढ़ कलेवा प्रारंभ किए गए हैं।

बिना पीसीसीएफ बने ही पीसीसीएफ की कुर्सी

आखिरकार वी.श्रीनिवास राव सात अफसरों को सुपरशीट कर छत्तीसगढ़ के वन बल प्रमुख बन गए। अभी तो वे प्रभारी बने हैं। कुछ महीने बाद स्थायी हो जाएंगे। श्रीनिवास राव को वन विभाग का मुखिया बनाने की चर्चा तो राकेश चतुर्वेदी के रिटायरमेंट के बाद शुरू हो गई थी। श्रीनिवास राव को वन विभाग की कमान सौपने के लिए फाइल भी चल पड़ी थी, लेकिन एक रिटायर आईएएस अफसर के वीटो के कारण संजय शुक्ला वन बल की पारी खेल पाए। इस बार श्रीनिवास राव ने किसी का दांवपेंच नहीं चलने दिया। 1990 बैच के आईएफएस श्रीनिवास राव अभी एडिशनल पीसीसीएफ हैं। पीसीसीएफ बने भी नहीं हैं और छत्तीसगढ़ वन विभाग के मुखिया बन गए और पीसीसीएफ बने छह लोग ताकते ही रह गए। सरकार ने पीसीसीएफ अतुल शुक्ला, सुधीर अग्रवाल,आशीष कुमार भट्ट, तपेश झा, संजय ओझा,अनिल राय और एडिशनल पीसीसीएफ अनिल साहू की वरिष्ठता को नजरअंदाज कर श्रीनिवास राव को छत्तीसगढ़ के वन विभाग के मुखिया की कमान सौंप दी। कहते हैं श्रीनिवास राव सर्वगुण संपन्न हैं , इस कारण सरकार ने चुनावी साल में उन पर दांव लगाया है। वैसे श्रीनिवास राव 2018 से वन विभाग के मलाईदार माने जाने वाले विंग कैम्पा के इंचार्ज हैं। श्रीनिवास राव के वन विभाग के मुखिया बनने के बाद कैम्पा का प्रभारी कौन बनेगा, इसकी भी चर्चा बड़ी जोरों पर है। कहते हैं अभी कैम्पा सरकार के लिए कमाऊ पूत जैसा है। चर्चा है कि पीसीसीएफ तपेश झा को वन्यप्राणी की जिम्मेदारी दे दी जाएगी। वन्यप्राणी संभाल रहे सुधीर अग्रवाल अपना पुराना काम कार्ययोजना ही देखते रहेंगे। एडिशनल पीसीसीएफ अरुण पांडे का कद बढ़ाए जाने की खबर है। श्रीनिवास राव अब अपनी टीम बनाएंगे।

सरकार के भरोसे के अफसर

2006 बैच के आईएएस अंकित आनंद अभी तक छत्तीसगढ़ विद्युत् मंडल के अध्यक्ष, मुख्यमंत्री के सचिव और ऊर्जा सचिव थे। अब सरकार ने उन्हें वित्त विभाग का भी सचिव बना दिया है। सरकार में सभी विभागों की चाबी वित्त विभाग के पास रहती है। वित्त विभाग समन्वय का भी काम करता है। विद्युत् मंडल और वित्त विभाग दोनों ही महत्वपूर्ण हैं। चुनावी साल में सरकार के फंड का मैनेजमेंट और लोगों को बिना कटौती के बिजली सप्लाई चुनौती से कम नहीं है। अब मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने भरोसा कर ही अंकित आनंद पर काम का बोझ बढ़ाया है। अब देखते हैं अंकित आनंद सभी विभागों का काम किस तरह से निपटाते हैं और दूसरे विभागों के साथ तालमेल कर चलते हैं।

टुटेजा को राहत से नई राह

आईएएस अफसर अनिल टुटेजा को ईडी की गिरफ्तारी से सुप्रीम कोर्ट की फौरी राहत मिलने से कइयों ने चैन की साँस ली। ईडी की

रवि भोई

गिरफ्तारी से भयभीत नेताओं और अफसरों को सुप्रीम कोर्ट के आदेश से नया रास्ता मिल गया है। वैसे कुछ नेता ईडी के खिलाफ कोर्ट गए थे, पर अब तक राहत अनिल टुटेजा को ही मिली है। कहते हैं अनिल टुटेजा ईडी की कार्रवाई के खिलाफ शुरू से आवाज बुलंद करते रहे और बिना डरे कोर्ट का दरवाजा खटखटाया, जिसमें उन्हें सफलता मिली। अब देखना होगा कि अनिल टुटेजा की राह पर चलते कितने लोग ईडी के खिलाफ कोर्ट जाते हैं और उन्हें कितनी सफलता मिलती है। सुप्रीम कोर्ट के रुख का ईडी की कार्रवाई पर कितना असर पड़ता है , इसका भी लोगों को इंतजार है। अनिल टुटेजा को मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के करीबी अफसरों में गिना जाता है। अनिल टुटेजा अभी उद्योग संचालक हैं और मई में रिटायर हो जाएंगे। माना जा रहा है कि रिटायरमेंट के बाद उन्हें संविदा नियुक्ति मिल जाएगी।

सपने देखते रह गए दीपक बैज

लगता है बस्तर के सांसद दीपक बैज प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष की कुर्सी का सपना देखते रह गए। कहा जा रहा है कि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के समर्थन के बाद भी दीपक बैज कांग्रेस हाईकमान का विश्वास जीत नहीं पाए और मोहन मरकाम को गद्दी से उतार नहीं पाए। खबर है कि दीपक बैज प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष बनने के लिए दिल्ली में कांग्रेस के बड़े नेताओं से मिले भी, लेकिन राज्य के एक मंत्री ने मोहन मरकाम के पक्ष में इतनी अधिक लॉबिंग की कि कांग्रेस के बड़े नेताओं ने फिलहाल तो प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष को चलने देने की राय बना ली है। अब राज्य में विधानसभा चुनाव को छह महीने बचे हैं, ऐसे में नया अध्यक्ष कितना कारगर होगा, इस पर सवाल उठ रहा है। लेकिन छत्तीसगढ़ में चुनाव के 2-3 महीने पहले भी प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष बदलने की परंपरा रही है। राजनीति में शह-मात का खेल तो चलता ही रहता है।

मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के सागौन बंगले जाने के मायने

कहा जाता है राजनीति में न तो कोई स्थायी दुश्मन होता है और न ही स्थायी दोस्त। राजनीतिक गुणा-भाग के अनुसार सब कुछ बदलता रहता है। छत्तीसगढ़ के प्रथम मुख्यमंत्री स्व. अजीत जोगी के 29 अप्रैल को आयोजित बरसी कार्यक्रम में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के मुख्य अतिथि होने का तो यही अर्थ लगाया जा रहा है। जोगी परिवार और मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के बीच छत्तीस के आंकड़े की बात हमेशा की जाती रही है। पर बरसी कार्यक्रम में सागौन बंगले में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की मौजूदगी के कई राजनीतिक मायने निकाले जा रहे हैं। स्व. जोगी का सतनामी समाज के वोट बैंक पर पकड़ होने की बात कही जाती रही है। परंपरागत रूप से यह वोट कांग्रेस के ही है। जोगी परिवार ने कांग्रेस से नाता तोड़कर ही अलग पार्टी बनाई है। 2018 के चुनाव में जोगी की पार्टी ने राज्य में पांच सीटें जीती थीं। तब अजीत जोगी जीवित थे। अब 2023 में फिर विधानसभा चुनाव होने हैं। कहीं जोगी पार्टी सभी सीटों में प्रत्याशी खड़ा कर कांग्रेस के वोट बैंक को प्रभावित न कर दे। मुख्यमंत्री के उनके निवास पर आयोजित कार्यक्रम में जाने से जोगी कांग्रेस के सधने की बात की जा रही है , तो कुछ जोगी परिवार के लिए चुनाव से पहले कांग्रेस के रास्ते खुलने की बात भी कर रहे हैं ।

रविंद्र चौबे के खिलाफ नारेबाजी

राज्य के कृषि मंत्री रविंद्र चौबे का साजा विधानसभा से चोली दामन का साथ है। वे

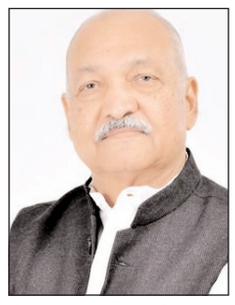

वहां से 1985 से विधायक हैं। 2013 को छोड़ दें तो वे हर चुनाव में वहां से जीत दर्ज करते रहे हैं। कहते हैं चौबे जी मंत्री बनने के बाद भी राजधानी में कम, साजा विधानसभा में अधिक समय बिताते हैं। हर तीज-त्यौहार में साजा विधानसभा में उनके कदम पड़ते ही हैं। पिछले दिनों उनके विधानसभा क्षेत्र के बिरनपुर में सांप्रदायिक तनाव का माहौल रहा। अब भी वहां निषेधाज्ञा लगा है। माहौल ख़राब होने के बाद रविंद्र चौबे अपने विधानसभा के इस इलाके में अब तक नहीं गए हैं। बताते हैं धारा 144 के हटने का इंतजार कर रहे हैं। पूर्व मुख्यमंत्री डॉ. रमन सिंह और अन्य भाजपा नेता वहां पहुँच रहे हैं। 28 अप्रैल को जब डॉ. रमन सिंह बिरनपुर जा रहे थे, तब बेमेतरा में उनसे मिलने आए कुछ लोगों ने रविंद्र चौबे के खिलाफ नारेबाजी की। अब नारेबाजी करने वाले भाजपा कार्यकर्ता हैं या आम जनता। यह तो 2023 के चुनावी नतीजे से पता चलेगा।

चुनाव के लिए भाजपा की माइक्रो तैयारी

2023 के विधानसभा चुनाव के लिए भाजपा ने माइक्रो लेवल पर तैयारी शुरू कर दी है। राज्य के बड़े-बड़े नेताओं को जमीनी हकीकत का पता लगाने फील्ड पर भेजकर रिपोर्ट मंगाई है तो छत्तीसगढ़ प्रभारी ओम माथुर भी धरातल पर उतरकर स्थिति को समझने में लगे हैं। राज्य के बड़े-बड़े नेताओं की जमीनी रिपोर्ट पर एक-दो दिन में समीक्षा होनी है, जिसके आधार पर रणनीति बनाई जाएगी। कहते हैं भाजपा चुनाव के लिए अलग-अलग टीम बनाकर काम करने वाली है। इसमें राजनीतिक टीम और टेक्निकल टीम अलग-अलग होगी। चुनाव के लिए पार्टी कार्यकर्ताओं में जोश भरने में लगी है , दूसरी तरफ कार्यकर्ता बैठकों से उबने लगे हैं। अब देखते हैं भाजपा में ईटिंग-मीटिंग- सीटिंग कब तक चलती रहती है या फिर जल्दी ही चुनावी मैदान में मोर्चा सँभालते हैं।

मई में प्रशासनिक फेरबदल

कहते हैं मई महीने में आईएएस अफसरों में फिर फेरबदल होगा। इस फेरबदल में कुछ जिलों के कलेक्टर फिर प्रभावित होंगे। परिवर्तन का असर कुछ बड़े , तो कुछ छोटे जिलों पर पड़ेगा। इसके अलावा एसपी-आईजी भी बदले जाएंगे। इस फेरबदल के फेर में आईएफएस अफसर भी आएंगे। कुछ जिलों के डीएफओ के अलावा सीएफ और सीसीएफ भी बदले जाएंगे।

भाजपा कार्यकर्ता लक्ष्य की ओर बढ़ रहे हैं- माथुर

रायपुर। छत्तीसगढ़ प्रदेश भाजपा मुख्यालय कुशाभाऊ ठाकरे परिसर में आज शाम आयोजित वरिष्ठ नेताओं की बैठक में विभिन्न विषयों पर चर्चा के साथ राज्य की राजनीतिक स्थिति में भाजपा की चुनावी संभावनाओं पर बिंदुवार विचार विमर्श किया गया तथा सुनिश्चित विजय का लक्ष्य प्राप्त करने रणनीतिक मंथन किया गया। बैठक में भाजपा प्रदेश प्रभारी ओम माथुर ने सभी वरिष्ठ नेताओं से बस्तर प्रवास सहित अन्य स्थानों के दौरे पर अनुभव साझा करते हुए कहा कि हर जगह पार्टी कार्यकर्ता विजय का लक्ष्य हासिल करने पूर्ण समर्पण के साथ जुटे हुए हैं। इस प्रवास में हर जगह कार्यकर्ताओं में उत्साह दिखाई दिया। भाजपा कार्यकर्ताओं की पार्टी है और हमें अपने कार्यकर्ताओं की शक्ति पर भरोसा है। सभी नेताओं को कार्यकर्ताओं का मैदानी मार्गदर्शन करना है। यह कार्य सुनियोजित तरीके से चल रहा है और हम निश्चित विजय के मार्ग पर आगे बढ़ रहे हैं।

पहली बार बाघ को लगाया गया रेडियो कॉलर

- अचानकमार में बढ़ेगा बाघों का कुनबा छोड़ी गयी आज एक मादा बाघिन
- बाघिन के विचरण की मॉनिटरिंग हेतु लगाया गया है रेडियो कॉलर

रायपुर। वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग द्वारा प्रदेश में वन्यप्राणियों के संरक्षण सहित वनों के विकास के लिए लगातार कार्य किये जा रहे हैं। इस कड़ी में 29 अप्रैल 2023 को प्रात: सूरजपुर वनमण्डल से 28 मार्च 2023 को रेस्क्यू की गई मादा बाघिन को पूर्णत: स्वस्थ्य होने के पश्चात राष्ट्रीय व्याघ्र संरक्षण प्राधिकरण की स्थापित मानक प्रचालन प्रक्रिया के तहत अचानकमार टायगर रिजर्व के उपयुक्त रहवास में छोड़ी गयी है।

गौरतलब है कि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की मंशा के अनुरूप वनमंत्री मोहम्मद अकबर के निर्देशन में अचानकमार टायगर रिजर्व में बाघों की जनसंख्या में वृद्धि किये जाने हेतु विशेष प्रयास जारी है। प्रधान मुख्य वन संरक्षक (वन्यप्राणी) सुधीर कुमार अग्रवाल के कुशल मार्गदर्शन में आज अचानकमार टायगर रिजर्व में बाघिन को रिलीज किया गया।

इस संबंध में प्रधान मुख्य वन संरक्षक (वन्यप्राणी) सुधीर कुमार अग्रवाल ने बताया है कि अचानकमार टायगर रिजर्व में निकटस्थ राज्य मध्यप्रदेश एवं महाराष्ट्र के टायगर रिजर्व से 2 मादा एवं 1 नर व्याघ्रों को लाने की प्रक्रिया चल रही है, इस बीच सूरजपुर वनमण्डल से रेस्क्यू की गई मादा बाघिन को अचानकमार टायगर रिजर्व में छोड़ा जाना एक सुखद संयोग है। मानक प्रचालन प्रक्रिया अनुसार 28 अप्रैल को वन्यप्राणी चिकित्सकों की टीम द्वारा बाघिन को रेडियो कॉलर लगाया गया एवं तत्पश्चात मादा बाघिन को उचित रहवास में सफ्लतापूर्वक छोड़ दी गई है ।

प्राकृतिक रहवास में मुक्त किये जाने के पश्चात आगामी एक माह तक मादा बाघिन के मूवमेंट का पता लगाने के लिए उपयुक्त निगरानी तंत्र स्थापित किया गया है। इस हेतु मैदानी अमले को पन्ना टायगर रिजर्व में विशेष रूप से प्रशिक्षित किया गया है। भारतीय वन्यजीव संस्थान के दो रिसर्च स्कॉलर एवं वन्यप्राणी चिकित्सकों की टीम भी विशेष रूप से तैनात की गई है। प्राकृतिक रहवास में छोड़े जाने के पूर्व क्षेत्र के ग्रामवासियों से भी चर्चा कर विश्वास में लिया गया है। इस मादा बाघिन के अचानकमार में स्थापित होने से अचानकमार में बाघों की संख्या में वृद्धि होने के लिए विभाग आशान्वित है।

छत्तीसगढ़/राजधानी
प्रमुख समाचार

कांग्रेस शासन में हो रही शासकीय भूमि की बंदरबांट- केदार गुप्ता

रायपुर। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता केदार गुप्ता ने कहा है कि छत्तीसगढ़ में जबसे कांग्रेस की सरकार आई है, शासकीय भूमि पर डाका डाला जा रहा है। श्री गुप्ता ने कहा कि ज़मीन माफिया अधिकारियों के साथ मिलीभगत करके सरकारी ज़मीन की बंदरबाँट कर रहे हैं। भाजपा प्रदेश प्रवक्ता श्री गुप्ता ने कहा कि अब तो सारी हदें लांघकर सरगुजा जिले की ग्राम पंचायत भटको में सरकारी भूमि खसरा नंबर 1290 से लेकर 1600 तक का पट्टा प्रदेश के कैबिनेट मंत्री अमरजीत भगत के निज सचिव भूपेन्द्र यादव ने अपने नाम पर बनवा लिया! श्री गुप्ता ने कहा कि यह तो एक ज़िले की बात है, जबकि प्रदेश के कई अन्य ज़िलों में भी यही स्थिति है। भारतीय जनता पार्टी यह मांग करती है कि छत्तीसगढ़ महतारी की जो शासकीय भूमि है, उसे भविष्य के लिए, नौजवानों, अस्पतालों, तालाबों, स्कूलों के लिए सुरक्षित रखा जाए। श्री गुप्ता ने कहा कि अभी तक सरकारी भूमि का आंबटन कहाँ कहाँ और किसे किस नियम के तहत किया गया है सरकार को इसकी जॉच करनी चाहिये और इसका खुलासा करन चाहिये।कांग्रेस की यह प्रदेश सरकार अपनी सम्पत्ति की रक्षा तक नहीं कर पा रही है, यह बेहद चिंता का विषय है , भविष्य में आबादी बढ़ रही है ऐसे में सार्वजनिक उपयोग के लिये भूमि कहाँ से लाऐंगें।

संघ अब नक्सलवाद के नाम से घड़ियाली आंसू बहा रही-कांग्रेस

रायपुर। प्रदेश कांग्रेस संचार विभाग के अध्यक्ष सुशील आनंद शुक्ला ने संघ नेता राजेंद्र प्रसाद के ऊपर

तंज कसते हुए कहा कि 15 साल के रमन सरकार के सहयोगी रहे संघ को सत्ता जाने के साढ़े 4 साल बाद याद आया कि बढ़े नक्सलवाद के लिए रमन भाजपा की सरकार जिम्मेदार है। 15 साल सत्ता के दौरान यही संघ के बड़े-बड़े नेता रमन सरकार के चाटुकार हुआ करते थे और आंखें मूंद कर बैठे थे और रमन सरकार के कमीशनखोरी, भ्रष्टाचार में हिस्सेदार भी थे अब जनता ने जब 15 साल बाद भाजपा को नकार दिया और 2023 के आम चुनाव नजदीक आ रहे हैं तब ऐसे में संघ के नेता जनता को भरवाने के लिए अपनी ही सरकार पर आरोप लगा रहे और खुद को पाक साफ बता रहे है। भाजपा की सरकारों की रिमोट आरएसएस के पास ही रहता है ऐसे में संघ रमन सरकार की जिम्मेदारी से खुद को बचा नहीं सकती। प्रदेश कांग्रेस संचार विभाग के अध्यक्ष सुशील आनंद शुक्ला ने संघ के बड़े नेता राजेंद्र प्रसाद से पूछा 15 साल में क्या संघ ने बढ़ते नक्सलवाद की चिंता क्यो नही की? नक्सल प्रभावित क्षेत्रों की जनता की शिक्षा स्वास्थ्य रोजगार उनके कानूनी अधिकार के बारे में क्यो नही सोचा? जो संघ सैकड़ों अनुषांगिक संगठनों का वरिष्ठ अपने आपको बताता है क्या उस संघ के पास रमन सरकार की नाकामी के संदर्भ में जानकारी नहीं आती रही है आखिर संघ की क्या मजबूरी थी? रमन सरकार आदिवासी वर्ग के ऊपर अत्याचार कर रहा था।

रमन सिंह, चंदेल व साव आरक्षण विधेयक पर हस्ताक्षर कराने राजभवन क्यों नही जाते?

रायपुर। प्रदेश कांग्रेस प्रवक्ता धनंजय सिंह ठाकुर ने कहा कि भाजपा को स्पष्ट करना चाहिए कि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की सरकार ने जनसंख्या के आधार पर एससी 32 प्रतिशत, ओबीसी 27 प्रतिशत, एससी 13 प्रतिशत और ईडब्ल्यूएस वालों को 4 प्रतिशत आरक्षण का लाभ देने के लिए 76 प्रतिशत आरक्षण संशोधन बिल पास किया है उसके पक्ष में है कि विरोध में? अगर भाजपा 76 प्रतिशत आरक्षण संशोधन बिल के पक्ष में है, प्रदेश की आरक्षित वर्ग की भला चाहती है तो पूर्व मुख्यमंत्री डॉ. रमन सिंह, नेता प्रतिपक्ष नारायण चंदेल और भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष अरुण साव अब तक राजभवन जाकर आरक्षण बिल पर हस्ताक्षर करने की मांग क्यों नहीं की? प्रदेश का हर वर्ग राजभवन जाकर उक्त बिल में हस्ताक्षर की मांग कर चुके हैं, सिर्फ भाजपा अब तक आरक्षण बिल को लेकर राजनीति कर रही है, बयानबाजी कर रही है लेकिन राजभवन नहीं जा रही है। कई बार सार्वजनिक तौर पर भाजपा और आरएसएस के नेताओं ने इस देश से आरक्षण को खत्म करने की बात कर चुके हैं और बीते 9 साल में केंद्र की भाजपा सरकार सरकारी संस्थाओं का निजीकरण कर आरक्षित वर्ग को मिलने वाले आरक्षण को खत्म कर रही है। इससे स्पष्ट हो जाता है कि भाजपा प्रदेश के 76 प्रतिशत आरक्षण बिल को लेकर षड्यंत्रकारी राजनीति कर रही है।

लोग मोदी के मन की बात सुनना नहीं चाहते, भाजपा जबरिया सुनवाने में लगी -कांग्रेस

रायपुर। देश की जनता के लिये प्रधानमंत्री मोदी के मन की बात बोझिल और उबाऊ रहता है। लोगों की

रुचि प्रधानमंत्री के मन की बात सुनने में नहीं रहती है। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष मोहन मरकाम ने कहा कि लोग मन की बात सुनते तो भाजपा को सुनाने के लिये पंडाल नहीं लगाना पड़ता। भाजपा प्रधानमंत्री की मन की बात सुनने के लिये तैयारी कर रही है उसके लिये अभियान चला रही है। जगह-जगह लोगों को एकत्रित करेगी इसका सीधा मतलब यह है कि प्रधानमंत्री की मन की बात को देश के लोग सुनना नहीं चाहते। उसका कारण यह है कि प्रधानमंत्री 99 एपिसोड तक जो भी मन की बात को कहा है वह जनता की मन की बात को नहीं कहा है, सिर्फ अपने मन की बात को कहा है। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष मोहन मरकाम ने कहा कि जनता जानना चाहती है जो वादे किये थे 100 दिन में महंगाई कम करेंगे, उसके बारे में कभी मन की बात नहीं की। हर साल दो करोड़ युवाओं को रोजगार देना नौ साल में लगभग 18, करोड़ युवाओं को रोजगार मिलना था आबादी के अनुसार छत्तीसगढ़ के 37 लाख युवाओं को रोजगार मिलना था अपने मन की बात में इसके बारे में कुछ नही कहते। 2022 तक किसानों की आय दुगुनी करने की बात की थी 2023 के 4 महीने पूरे हो गये किसानों की आय के बारे प्रधानमंत्री कुछ नही कहते जनता अपने मन की बात उनके मुंह से सुनना चाहती है।

भाजपा महिला मोर्चा को दिल्ली में आंदोलन करना चाहिए - वंदना राजपूत

रायपुर। भाजपा महिला मोर्चा अध्यक्ष शालिनी राजपूत के शराबबंदी के बयान पर

पलटवार करते हुए प्रदेश कांग्रेस प्रवक्ता वंदना राजपूत ने कहा कि महिलाओं की वास्तविकता में चिंता है तो भाजपा के महिला मोर्चा को दिल्ली में आंदोलन करना चाहिए। महिला मोर्चा के नेत्रियों के लिये अच्छा अवसर है विधानसभा 2023 और लोकसभा 2024 में चुनाव है। नरेंद्र मोदी को 2014 के वादा याद दिलाने चाहिए। मोदी ने 100 दिन में महंगाई कम करने का वादा किया था लेकिन महंगाई आज बेलगाम हो गई है। मोदी ने काला धन लाने का वादा किया था उसका क्या हुआ, सबके बैंक खाता में 15-15 लाख देने का वादा मोदी जी ने किया था, प्रतिवर्ष 2 करोड़ बेरोजगारों को रोजगार देने का वादा, किसानों की आय दुगुनी करने का वादा। प्रदेश कांग्रेस प्रवक्ता वंदना राजपूत ने कहा कि प्रदेश में 15 साल भाजपा की सरकार ने छत्तीसगढ़ को गर्त में धकेलने का काम किये और इसमें भाजपा महिला मोर्चा की भी सहभागिता थी। शराब के सरकारीकरण करके पूर्ववर्ती भाजपा सरकार शराब बेचने का काम किया। 2016 में छत्तीसगढ़ ने प्रति व्यक्ति शराब के खपत के मामले में गोवा को भी पीछे छोड़ा था।

आप छत्तीसगढ़ के पदाधिकारियों काशपथ ग्रहण समारोह संपन्न

रायपुर। आम आदमी पार्टी छत्तीसगढ़ के प्रदेश में नव नियुक्त पदाधिकारियों का आज रायपुर के शहीद स्मारक भवन में कार्यक्रम रखा गया। आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संगठन महामंत्री और राज्य सभा सांसद डॉ. संदीप पाठक कार्यक्रम के मुख्य अतिथि रहे।

उन्होंने अपने उदबोधन में कहा कि ये जो पद है आपको किसी ने दिया नहीं है वो आपकी गाढ़ी कमाई का फल है। अभी हमने जो 1000 के आसपास प्रदेश में शपथ लें रहें हैं ये काम अभी पूरा नहीं हुआ है आगे और कई हजार साथी आप पार्टी से जरूर शपथ लेंगे। हमारा उद्देश्य स्पष्ट होना चाहिए। हम सभी को प्रदेश में ईमानदार सरकार बनानी है। सभी को ध्यान रखना है की पद मिलने पर आप अहंकार मत

लाइए। आम लोगों को जोड़ते जाइये आपका कुनबा अपने आप कब बड़ा हो जायेगा आपको पता भी नहीं चलेगा। अब चुनाव में छह महीने का ही समय रह गया है।

आम आदमी पार्टी की बिजली शिक्षा और स्वास्थ्य की जनहित योजनाओं का लाभ छत्तीसगढ़ की जनता को पहुँचाते हुए इस बार प्रदेश में आप की सरकार बनाना है। छत्तीसगढ़ में चहूँ ओर विकास हो और छत्तीसगढ़ खूब खुशहाल हो। छत्तीसगढ़ प्रभारी संजीव झा जी कहा कि मुझे पुरानी विश्वास है कि आपके कंधों पर नयी राजनीति में दिशा दिलाने नई जिम्मेदारी है। प्रदेश में एक साल के प्रयास के बाद आज छत्तीसगढ़ में प्रदेश से लेकर ब्लॉक तक पूरी टीम तैयार है। आपकी मेहनत, आपकी क्षमता और आपके कम करने का जज्बा किसी पद की मोहताज नहीं होती। अगर आप छत्तीसगढ़ की जनता तक आम आदमी पार्टी का मिशन पहुंचा सकतें हैं तो आप किसी भी पद से भी बहुत बड़े हैं। उन्होंने कहा कि महज 10 साल पहले जो आप पार्टी की योजनाओं का मज़ाक उड़ाते थे आज कर्नाटक चुनाव में मुफ्त बिजली और स्वास्थ्य की बात कर रहें हैं।आज प्रदेश में हमारा पुरानी संगठन तैयार है। हमें छत्तीसगढ़ की जनता के बीच कि कड़ी बनना है और प्रदेश में आम आदमी पार्टी की सरकार बनाना है। छत्तीसगढ़ के आप प्रदेश अध्यक्ष कोमल हुपेंडी ने कहा कि 22 साल से रत्न गर्भा छत्तीसगढ़ को छला जा रहा है आपके कर्मों का फल है और भगवान ने हमें उनके अधिकारों और न्याय के लिए चुना है और इस जिम्मेदारी को निभाते हुए छत्तीसगढ़ में निर्णायक बदलाव की ओर बढ़ने का समय आ गया है और प्रदेश में आम आदमी पार्टी की ईमानदार सरकार बनाएंगे।

पीसीसी अध्यक्ष ने बिलासपुर संभाग की बूथ कमेटियों की गठन की समीक्षा किया

रायपुर। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष मोहन मरकाम, अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के सचिव छत्तीसगढ़ प्रभारी डॉ. चंदन यादव ने बिलासपुर संभाग के विधायकों, जिला अध्यक्ष, ब्लॉक कांग्रेस अध्यक्षों की बैठक लिया। बैठक में सभी ब्लॉकों में बूथ कमेटियों के गठन की समीक्षा किया गया। जिन ब्लॉक अध्यक्षों ने अपने क्षेत्र के बूथ कमेटियों की सूची को जमा किया। उनका वहीं पर प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष ने फोन करके भौतिक सत्यापन किया। अभी तक जिन ब्लॉक कांग्रेस

कमेटियों ने अपने क्षेत्र की बूथ कमेटियों का गठन नहीं किया है उनसे कहा गया है कि एक सप्ताह के अंदर अनिवार्य रूप से बूथ कमेटियों का गठन कर प्रदेश कांग्रेस को जमा करें। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष मोहन मरकाम ने कहा कि जिन ब्लॉकों में बूथ कमेटियों का गठन समय पर नहीं होगा वहां पर पीसीसी पदाधिकारी भेजे जायेंगे। मई माह के प्रथम सप्ताह से बूथ कमेटियों के प्रशिक्षण का काम शुरू किया जायेगा। कार्यक्रम में प्रदेश कांग्रेस उपाध्यक्ष चुन्नीलाल साहू, प्रेमचंद जायसी, महामंत्री एवं बूथ प्रबंधन प्रभारी अरूण सिसोदिया, महामंत्री पियूष कोसरे, विधायकगण के.के ध्रुव, मोहित केरकेट्टा, उत्तरी जांगडे, रश्मि सिंह, जिला कांग्रेस अध्यक्ष विजय पाण्डेय, विजय केशरवानी एवं ब्लाक कांग्रेस अध्यक्षगण उपस्थित थे।

आर.एन.आई.रजि. क्र. CHHHIN/2021/80529, स्वत्वाधिकारी, मुद्रक एवं प्रकाशक- शशांक शर्मा द्वारा मिशन मीडिया प्रा. लि., प्रेस कॉम्प्लेक्स, रजबंधा मैदान, रायपुर (छ.ग.) 492001 से मुद्रित एवं 29/1110, सेवती स्मृति, आजाद चौक, रायपुर (छ.ग.) 492001 से प्रकाशित। संपादक-शशांक शर्मा, मो. 94255-20531.